▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

पौष–माघ 2081, जनवरी 2025

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक

स्वदेशी मेला - कर्नाटक

स्वदेशी - महाकुंभ

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI Patrika

स्वदेशी पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–33, अंक–1

पौष–माघ 2081 जनवरी 2025

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–06

आर्थिक विवेक की कसौटी पर डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **चिंतन**
वर्तमान वैश्विक, आर्थिक परिदृश्य एवं भारतीय चिंतन .... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

11 **आर्थिकी**
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने से साकार होगा विकसित भारत का सपना .... अनिल तिवारी

13 **गणतंत्र दिवस**
प्रजातंत्र और जन भागीदारी .... शिवनंदन लाल

16 **बहस**
ताकि बरकरार रहे शिक्षा और शिक्षक की गुणवत्ता! .... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

18 **बजट चर्चा**
वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को देनी होगी राहत .... प्रहलाद सबनानी

20 **जल–संकट**
भूजल स्तर में गिरावट और गुणवत्ता का सवाल .... स्वदेशी संवाद

22 **समीक्षा**
रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता .... विनोद जौहरी

24 **विचार**
'वन नेशन, वन एग्जामिनेशन' से बढ़ेगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता .... गणेश गौतम

26 **मुद्दा**
गिरती प्रजनन दर भविष्य का नया संकट .... विजय गर्ग

28 **विश्लेषण**
सांस्कृतिक परम्पराओं के चलते पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाता भारत .... स्वदेशी संवाद

30 **शिक्षा**
नो डिटेंशन पॉलिसी के खात्मे से शिक्षा में होगा सुधार! .... सुशील कुमार महला

32 **दिव्य विभूतियां**
ईश्वर के आंनद, स्वामी विवेकानन्द .... हेमेन्द्र क्षीरसागर

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

महाकुंभ 2025

महाकुंभ मेला, एक 144 वर्षीय धार्मिक तीर्थयात्रा, भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक वरदान प्रदान करता है। इस आयोजन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के भारी संख्या में आगमन से महत्वपूर्ण राजस्व और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। भारत का पर्यटन क्षेत्र, जो जीडीपी का एक प्रमुख योगदानकर्ता है, को भी काफी लाभ होने की संभावना है। करोड़ों लोगों को आकर्षित करने वाला यह महाकुंभ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित और असंख्य नौकरियां पैदा कर सकती है।

पिछले कुंभ मेले (12 वर्ष में आयोजित) इस आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं। 2013 के प्रयागराज कुंभ मेले ने 12,000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2019 में आयोजन अर्द्ध कुंभ में 5 करोड़ श्रद्धालूओं ने भागीदारी की थी, जिससे 1,200 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया। 2025 के महाकुंभ से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 2 लाख करोड़ रूपये तक बढ़ावा मिलने का अनुमान है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं के व्यापार (17,310 करोड़ रू. अनुमानित) और आतिथ्य (2,800 करोड़ रू. अनुमानित) जैसे विशिष्ट क्षेत्र पर्याप्त विकास के लिए तैयार हैं।

हालांकि, इस तरह के विशाल आयोजन में तार्किक चुनौतियां पेश आती हैं। प्रभावी बुनियादी ढांचा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और पर्यावरणीय स्थिरता महत्वपूर्ण हैं। केवल सावधानीपूर्वक तैयारी के माध्यम से ही भारत महाकुंभ मेले की आर्थिक क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठाया जा सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित, पर्यटन को बढ़ावा और व्यापक लाभ उत्पन्न किया जा सकता है।

विजीत कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा हैं, जो युवा मन में उद्देश्य के प्रति जुनून की भावना प्रज्वलित करते रहते हैं।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

सरकार गतिशील भू–राजनीतिक विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों को एक आधुनिक युद्ध मशीन में परिवर्तित कर रही है।

राजनाथ सिंह
रक्षामंत्री, भारत

हम डीपीडीपी नियमों को और अधिक परिष्कृत करेंगे, ताकि प्रौद्योगिकी की शक्ति को बच्चों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें अनेक नुकसानों से बचाया जा सके। यदि आवश्यकता हुई तो क्षेत्र–विशेष के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

अश्वनी वैष्णव
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत

संपादकीय

स्वास्थ्य परिदृश्य में सुखद बदलावः सरकार ले रही है अधिक जिम्मेदारी

केंद्रीय बजट 2025–26 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर 103280 करोड़ रुपये का व्यय आवंटित किया गया है। यदि हम पिछले 11 वर्षों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर व्यय में 8.3 गुना वृद्धि हुई है, जो 2014–15 में 12482 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट 2025–26 में 103280 करोड़ रुपये हो गया है। इस अवधि के दौरान केंद्रीय बजट का आकार मुश्किल से 2.8 गुना ही बढ़ा है। दस साल पहले, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि 1990–91 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय (जिसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पोषण, बाल और विकलांग कल्याण शामिल होते हैं) सकल घरेलू उत्पाद का 2.36 प्रतिशत था। वैसे तो भारत में सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान कभी भी उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन एलपीजी से पहले के दौर में भी इन सुविधाओं को सरकारी नीति निर्माण के केंद्र में रखा जाता रहा। एलपीजी नीतियों के तहत निजीकरण के आगमन के साथ ही लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ दिया गया। 2014–15 से पहले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती जा रही थीं, उनमें काफी सुधार होना प्रारंभ हुआ है, जिससे लोगों द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च को कम करना संभव हो पाया है। हम देखते हैं कि 2004 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय 4.2 प्रतिशत था, और इसमें से 2.59 प्रतिशत निजी जेब से किए जाने वाले खर्च का था। चिंता की बात यह थी कि सार्वजनिक व्यय भयानक रूप से कम था, देश के सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से भी कम। अध्ययन बताते हैं कि जेब से किए जाने वाले उच्च व्यय के गंभीर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिससे ग्रहस्थों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है; विशेष रूप से इसने समाज के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों को ज़्यादा प्रभावित किया है। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग के कई लोगों को जबरन गरीब बना दिया गया। व्यापक आर्थिक स्तर पर, इसने गरीबी उन्मूलन में सरकारी प्रयासों को विफल किया और सामान्य आर्थिक कल्याण को निम्न स्तर पर ला दिया। पिछले एक दशक में सरकार द्वारा सकारात्मक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के कारण, गैर–संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के बावजूद, जेब से होने वाले खर्च में लगातार कमी आ रही है, जिससे आम जनता और खास तौर पर गरीबों को राहत मिली है। 2013–14 तक जेब से होने वाला खर्च करीब 2.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा। 2004–05 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जेब से होने वाला खर्च 2.58 था, जो 2013–14 में भी 2.43 पर बना रहा, जबकि तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में बड़े–बड़े दावे किए थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ, हमने निजी जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय में धीरे–धीरे गिरावट देखी है। हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जेब से किये जाने वाले व्यय में अधिक तेजी से गिरावट 2015–16 के बाद देखी गई, क्योंकि यह 2015–16 में 2.32, 2019–20 में 1.54, 20–21 में 1.66 और 21–22 में 1.55 थी।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि भारत में सरकारें स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने की बढ़ती जरूरत को पूरा करने की ओर संवेदनशील हैं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ रहा है क्योंकि 1950–51 में यह भारत के जीडीपी का 0.22 प्रतिशत था, 1975–76 में 0.81, 1990–91 में 0.96, 1995–96 में 0.88, 2005–06 में 0.96। 2007–08 से 2013–14 के बीच यह आंकड़ा कुछ हद तक 1 के करीब पहुंच रहा था। हालांकि, 2015–16 के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि 2015–16 में यह जीडीपी का 1.02 था, 2016–17 में 1.17 और 17–18 में 1.35, 18–19 में 1.28, 19–20 में 1.35, 20–21 में 1.6 और 21–22 में 1.84 था। भारत के मामले में, आयुष्मान भारत की शुरूआत ने निजी जेब से स्वास्थ्य खर्च कम करने में काफ़ी मदद की है। आयुष्मान भारत योजना में दो खंड शामिल हैं– एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन और निर्माण से संबंधित है जिसे प्रधान मंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) के रूप में जाना जाता है और दूसरा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की दिशा में है जिसे आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2024 तक, कुल 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) या तो स्थापित किए गए थे या मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप–स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) से उन्नत किए गए।

आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई)। इसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य खर्चों के लिए 5 लाख तक के स्वास्थ्य खर्चों को वहन करना है। शुरुआत में यह समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए ही था। भारत सरकार ने 2018 में इसके लिए 1998 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो आगे बढ़कर 2022 में 6185 करोड़ रुपये हो गए, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है। इसके अलावा, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अस्पतालों में मूल्य सीमा भी तय की है, लेकिन गैर–कार्ड धारकों के लिए वास्तव में कीमत बहुत अधिक है। इसके अलावा, पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य देखभाल की लागत वैसे भी बहुत सस्ती है, यही कारण है कि भारत उनके लिए एक आकर्षक गंतव्य है। यह सच है कि इन वर्षों के दौरान हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, सार्वजनिक बीमा आधारित, सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं और नैदानिक सेवाएं प्रदान करके, कल्याण की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देकर समान स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की दिशा में प्रयास किया है। इसके साथ–साथ हमें अपने चिकित्सा उद्योग को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में नए अत्याधुनिक नवाचार और तकनीक विकसित की जा सकें जो दुनिया भर में बीमारियों की बदलती प्रकृति की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह कई तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है। यह एक स्वस्थ कार्यबल प्रदान करेगा, गरीबी को कम करने में मदद करेगा, साथ ही विदेशी मुद्रा जुटाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार, इस प्रयास में, सरकारों के दोनों स्तरों को तालमेल में काम करने की आवश्यकता है।

आर्थिक विवेक की कसौटी पर डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पिछले कार्यकाल से ही अपनी अप्रत्याशितता के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद और सत्ता संभालने के बाद फिर से अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं।

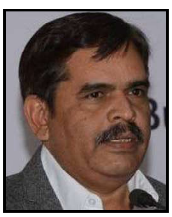

दुनिया के ज़्यादातर अर्थशास्त्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के फ़ैसलों से सहमत नहीं हैं और उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रथम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़ैसलों से न सिर्फ़ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका बाक़ी दुनिया से अलग–थलग पड़ जाएगा

– डॉ. अश्वनी महाजन

टैरिफ युद्ध

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया के दूसरे देश अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं, इसलिए वे भी अमेरिका में आने वाले आयातों पर टैरिफ बढ़ाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले सामान को रोका जा सके और देश में उत्पादन को बढ़ावा मिले। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल से ही वे लगातार यह कहते रहे हैं कि वे अमेरिका की जंग खा रही फैक्ट्रियों को फिर से चालू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत, चीन, ब्राजील और कई दूसरे देशों के आयात शुल्क बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे इन देशों से आयात पर भी भारी टैरिफ लगाएंगे। उन्हें लगता है कि अमेरिका में आयात शुल्क कम होने की वजह से अमेरिकी उद्योगों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि देश का उत्पादन विदेशों में चला जाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यह भी कहते हैं कि एक तरफ अमेरिका के लोगों का रोजगार खत्म होता है, वहीं दूसरी तरफ देश को राजस्व का नुकसान होता है; और आयात शुल्क से होने वाली आय की हानि की भरपाई के लिए, उन्हें अमेरिकी लोगों पर अधिक कर लगाना पड़ता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वह आयकर खत्म कर देंगे और इसकी भरपाई आयात शुल्क से करेंगे। गौरतलब है कि अपने पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर अमेरिकियों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की थी। लेकिन उस समय भले ही अमेरिका ने प्रतीकात्मक रूप से टैरिफ बढ़ाए थे और कई कदम उठाए थे, जैसे कि कई भारतीय उत्पादों को जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) से बाहर करना इत्यादि; लेकिन अमेरिका में आने वाले अधिकांश आयातों पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का बार–बार आयात शुल्क बढ़ाने पर जोर देना और आयकर खत्म करने की घोषणाएं असामान्य लगती हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाईडेन के उस फैसले को पलटने की भी बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार अति धनी लोगों पर आयकर बढ़ा दिया गया था।

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह अन्य देशों पर कर लगाएंगे और अमेरिकियों पर कर कम करके उन्हें अमीर बनाएंगे। कर कम करने के संबंध में उनका इरादा व्यक्तियों और परिवारों की डिस्पोजेबल आय को बढ़ाना और अमेरिका को समृद्ध बनाना है। वे याद दिलाते हैं कि 1870 से 1913 तक का काल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे अच्छा काल है, जब टैरिफ आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू थी और अमेरिका टैरिफ लगाकर भारी

राजस्व कमाता था।

विदेशों में चली गई अमेरिकी कंपनियों को सलाह

आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को विदेशी भूमि से अपनी उत्पादन इकाइयां अमेरिका में स्थानांतरित करने की सलाह भी दी है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे उच्च टैरिफ और आयकर का भुगतान करने से बच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना घ्है कि कम टैरिफ के कारण देश की जहाज और रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। उनका कहना है कि एक समय था जब अमेरिका हर दिन एक जहाज बनाता था, लेकिन अब जहाज निर्माण लगभग विदेश में स्थानांतरित हो गया है।

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो अमेरिकी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां वापस अमेरिका लाएगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स, सेमी–कंडक्टर और स्टील निर्माण में।

पर्यावरण की कीमत पर अमेरिका को महान बनाने की तैयारी

एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका मानना है कि पर्यावरण की रक्षा के नाम पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में उन्होंने सभी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों को हटाने का भी आदेश दिया है, क्योंकि ये जमीन को नष्ट करते हैं और जमीन की कीमतों को कम करते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने दुर्लभ खनिज उत्पादों के खनन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि अमेरिका में दुर्लभ खनिज उत्पादों का बड़ा भंडार है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इनके खनन में बाधाएं पैदा की जाती हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे इन बाधाओं को दूर करने और इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों का निष्कर्ष यह है कि वे अमेरिकी कामगारों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका की व्यापार प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकी लोगों की आय में सुधार होगा और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। लेकिन क्या यह संभव होगा? इसका मूल्यांकन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर करना होगा।

सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वस्तुओं के आयात पर टैरिफ बढ़ाने से देश में उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि देश के पास वर्तमान में उन वस्तुओं के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता हो। यह सही है कि पहले अमेरिका में ज्यादातर वस्तुओं का उत्पादन होता था। स्टील, जूते, कपड़े, रक्षा उपकरण, जहाज, दवाइयां, रसायन, सभी तरह के उत्पाद अमेरिका में बनते थे। लेकिन अमेरिकी उद्योगों की उच्च लागत और सस्ते आयातित विकल्पों के कारण वे सभी उद्योग बंद हो गए और आज अमेरिका इन सभी वस्तुओं के लिए ज्यादातर विदेशी देशों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में आयात शुल्क बढ़ाने से उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इससे आयातित विकल्प महंगे जरूर हो जाएंगे और इस तरह महंगाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकियों पर और बोझ पड़ेगा।

दूसरा, अगर अमेरिका आयकर खत्म करने का फैसला करता है, तो इसकी भरपाई बजट घाटे में बढ़ोतरी से करनी होगी, क्योंकि आयात शुल्क में बढ़ोतरी आयकर संग्रह में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में बजट घाटे में बढ़ोतरी के कारण अमेरिका में महंगाई और बढ़ सकती है।

तीसरा, महंगाई बढ़ने के कारण ब्याज दरें भी बढ़ानी होंगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले ही उच्च ब्याज दरों की मार झेल रही है, घरों और अन्य टिकाऊ वस्तुओं जैसे कार और अन्य घरेलू उपकरणों की मांग प्रभावित हुई है। यदि यह मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मांग और भी बाधित हो सकती है।

चौथा, डोनाल्ड ट्रम्प का पेरिस पर्यावरण समझौते से हटने का निर्णय; और देश में पर्यावरण सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के उत्पादन को रोकने का निर्णय किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन समाप्त करने के उनके निर्णय से अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास दुनिया से ज्यादा अमेरिका के हित में हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी विकास से अमेरिका को लाभ हो सकता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। जिस गति से अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ रहा था, अब उस पर असर पड़ेगा।

दुनिया के ज़्यादातर अर्थशास्त्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के फ़ैसलों से सहमत नहीं हैं और उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रथम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़ैसलों से न सिर्फ़ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका बाक़ी दुनिया से अलग–थलग पड़ जाएगा, साथ ही महंगाई और आर्थिक मंदी के कारण अमेरिकी लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही साबित होंगे या अर्थशास्त्री। ❑❑

वर्तमान वैश्विक, आर्थिक परिदृश्य एवं भारतीय चिंतन

वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है, जहाँ बाज़ारवादी प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पर्यावरण दूषित एवं विषाक्त होता जा रहा है। पूंजीवाद और मार्क्सवाद के शिकंजों ने एक तरफ़ आर्थिक विषमता और दूसरी ओर समाज में घोर असंतोष तथा असहिष्णुता का वातावरण पैदा किया है। साधारण जनता ग़रीबी, मंहगाई, बेरोजगारी तथा कर्ज के बोझ से परेशान है। समाज में नैतिक मूल्यों, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है। कृषि उत्पादों में जिस प्रकार रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है और इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे नई किस्म की प्राणघातक बीमारियों का जन्म हो रहा है। राष्ट्रों के बीच सामाजिक–राजनैतिक तनाव बढ़ते रहने से तीसरे विश्व युद्ध के ख़तरों के बादल मंडरा रहे हैं और एक दूसरे के बीच अस्त्र–शस्त्रों की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना सामरिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है?

उपरोक्त सभी विपरीत समस्याओं के समाधान के लिए विवेकपूर्ण चिंतन के साथ एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा, जहाँ गरीबी और बेरोजगारी मुक्त स्वावलम्बी समाज हो। जहाँ आर्थिक विषमता नगण्य हो और प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग हो, यानि दोहन और पोषण दोनों होगा पर शोषण नहीं होगा। हमें नैतिक मूल्यों, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था बनानी होगी और आर्थिक भ्रष्टाचार की जड़ मूल समाप्त करना होगा।

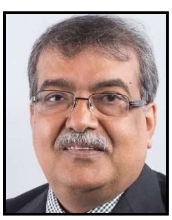

हमारे विकास का लक्ष्य उपभोक्तावादी संस्कृति नकारते हुए एक ऐसा वैकल्पिक आर्थिक दर्शन दुनिया के सामने रखना है, जिससे प्रकृति का शोषण न हो, पर्यावरण संतुलित रहे।

–डॉ. धनपत राम अग्रवाल

आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर कृषि तथा पशु पालन जीविका का आधार था और ग्राम्य जीवन एक स्वावलंबी आधार पर सुखी जीवन था। उन्नीसवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद आदि भौतिकवादी दृष्टिकोण की मान्यता बढ़ने लगी और समाज धनी और ग़रीब की आर्थिक विषमता में बंटने लगा। मानवगत और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बढ़ने लगा। बीसवीं शताब्दी ने दो–दो विश्वयुद्ध देखें और दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक पर पूंजीवाद और बाजारवाद हावी था और दूसरे पर साम्यवाद या समाजवाद का दबाव बढ़ा। नये–नये प्रतिष्ठान बने, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और विश्व बैंक प्रमुख हैं। इन संस्थानों पर भी बाज़ारवादी ताकतों का प्रभुत्व बना रहा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह अमेरिकी बाज़ारवादी कूटनीतियों ने जगह बना ली।

19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दरम्यान नये–नये आविष्कार होते रहे और इसका पूरा लाभ पाश्चात्य देशों को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत तथा

अन्य उपनिवेश द्वारा नियंत्रित भू–भागों के प्राकृतिक तथा पूंजीगत संसाधनों की लूट से इकट्ठा किया गया धन उनके पास था। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और यूरोप धनी राष्ट्र बन गये, जिन्हें बाद में जी–7 और ओईसीडी ग्रुप से जाना जाने लगा। एशिया के कुछ छोटे–छोटे देश जापान की औद्योगिक नीति का पालन करते हुए अपनी मेहनत और राष्ट्रवादी नीतियों के आधार पर अपने घरेलू उद्योग तथा निर्यात के आधार पर अच्छी तरक्की कर पाये। इनमें से मुख्यरूप से मलेशिया, सिंगापुर, फ़िलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि हैं, किंतु इन्हें भी 1997 के आसपास आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा तथा जापान भी लंबे समय तक आर्थिक मंदी को झेलता रहा और आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इन दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों की आर्थिक नीतियों पर कहीं न कहीं पाश्चात्य वित्तीय संस्थाओं की एकतरफा और खुली आज़ादी की अधिकता कारण बनी थी। आज भारत में भी इस तरह की वित्तीय संस्थाएं काफी तेजी से काम कर रही हैं, जिससे हमारे पूंजी बाज़ार में तथा विदेशी मुद्रा के लेन देन से कुछ अनिश्चितता बढ़ने लगती है।

राजनैतिक उपनिवेशवाद के द्वितीय महायुद्ध के खत्म हो जाने के बाद आर्थिक उपनिवेशवाद का जन्म हुआ जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी डालर की कूटनीतिक चाल द्वारा दुनिया के अर्थ तंत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। आईएमएफ को हथकंडा बनाकर गोल्ड स्टैण्डर्ड की जगह एक झूठे आश्वासन के आधार पर कि वह डालर के बदले एक निर्धारित सोने की मात्रा देगा और उसने लिखित रूप में 35 डालर प्रति औंस सोने की क़ीमत निर्धारित की, अर्थात् जो भी देश जब कभी चाहे, अमरीकी फेड रिज़र्व से इस क़ीमत पर डालर के बदले सोना ले सकता है। वर्ष 1973–74 में कच्चे तेल के दाम एकाएक चार गुना बढ़े। इजिप्ट और इजरायल युद्ध के बाद जैसे ही अमेरिका ने इजरायली मदद की घोषणा की, अरब देशों ने कच्चे तेल की आपूर्ति पर रोक लगा दी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल का दाम जनवरी 1974 में 2.90 अमरीकी डालर से बढ़कर 11.65 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया। इसी बीच राष्ट्रपति निक्सन ने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका 35 डालर के बदले एक औंस सोना देने के अपने वायदे को एकतरफ़ा ख़त्म करता है। इससे दुनिया के सभी देश नाराज तो हुए, किंतु किसी के पास अमेरिकन डालर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने सऊदी अरब से पेट्रो डालर की एक सन्धि पर 8 जून 1974 पर हस्ताक्षर किये। यह एक बहुत गहरी कूटनीतिक चाल थी, जिसके आधार पर अमेरिका ने अपने 1944 में डालर के बदले सोना देने के वचन से इनकार कर देने के बावजूद डालर दुनिया की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का खिताब अपने हाथ में आज भी रखा हुआ है, जबकि 9 जून 2024 को पेट्रो डालर समझौता रद्द हो गया है। ऐसी परिस्थिति में चीन, भारत तथा अन्य विकासशील देश 1944 के ब्रिटन वुडसिस्टम से बाहर निकल कर एक नई अर्थव्यवस्था और एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच हाल ही में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो बैठक हुई है, उसमें यह तय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनियोग के मापदंडों को नई दिशा देनी होगी तथा डालर के वर्चस्व को तथा अमेरिका की मनमानी को नियंत्रण में करने के लिये विश्व बैंक तथा आईएमएफ के संचालन को ज़्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना होगा।

वर्तमान बाज़ारवादी पूंजीवाद के दोषों की वजह से सारी दुनिया में किसी न किसी रूप से आर्थिक संकट के बादल मंडराते रहते हैं। 1973–74 के पेट्रो डालर समझौते से वित्तीय संस्थाओं के पास डालर की इतनी आपूर्ति हो गई कि उन्होंने लैटिन अमेरिकन देशों को प्रलोभन देकर बड़ी मात्रा में ऋण दिया जिसको वे वापस नहीं कर पाये और 1980 के दशक में भयंकर आर्थिक संकट में फँस गये। अमेरिकी सरकार ने आईएमएफ से मिलकर उनकी आर्थिक संप्रभुता की अस्मिता की अवहेलना करते हुए नई–नई आर्थिक शर्तों पर अलग–अलग योजनाओं को लागू करवाया। इनमें से बेकर प्लान, ब्रेडी प्लान और फिर वाशिंगटन कंसेंसस आदि के द्वारा 1982 से ऋण देय संकट को दूर करने का उपाय बताया। इस प्रकार आर्थिक सुधार के नाम से भारत में भी 1990–91 में भूमण्डलीकरण और वैश्विकरण के नाम पर विदेशों से लिये गये ऋण और उससे उपजे व्यापार घाटे के संकट से उबरने का एकमात्र उपाय बताया गया। ज़ल्दबाजी में लिये गये बहुत से निर्णय आज भी हमारे कृषि क्षेत्र और लघु उद्योगों के लिये नासूर बने हुए हैं और पिछले लगभग 35 वर्षों के आर्थिक सुधारों के नाम पर किये गये नीति निर्णय हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुओं के आयात और विदेशी तकनीक तथा विदेशी पूंजी के दबाव से हमारी आर्थिक संप्रभुता पर दुष्प्रभाव बनाये हुए हैं।

भारत को स्वाधीन हुए 78 वर्ष पूरे हो गये हैं। आज हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हैं। हमारा लक्ष्य है कि आगामी 2047 तक एक समृद्धशाली और वैभवशाली राष्ट्र बने जो पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो और जो ग़रीबी तथा बेरोजगारी से मुक्त हो। जब हम स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे कर लें, उस समय हम दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जायें तथा हमारे पुराने खोये हुए गौरव को

प्राप्त कर विश्व गुरु कहलायें। ज्ञान और विज्ञान, साहित्य, शिक्षा और कला के क्षेत्र में हमारी ख्याति दुनिया भर में अग्रणी स्थान पर हो।

विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने का जो लक्ष्य है, उसके लिये दो बातें ध्यान में लानी होगी। प्रथम, हमारे पास उपलब्ध साधनों का आंकलन और दूसरा विकास की अवधारणा और स्व आधारित वैचारिक अधिष्ठान। हमारे आर्थिक संसाधन तीन प्रकार के हैं– प्राकृतिक, पूंजीगत और मानवगत। आज के वैज्ञानिक और ज्ञान आधारित नवाचार तथा तकनीकी युग में मानव संसाधन सबसे ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। जितने भी नये आविष्कार हैं वे सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। इसके साथ ही हरित तकनीक और हरित अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सृजन के सौर तथा अन्य स्रोतों से हरित ऊर्जा संबंधी नवाचारों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम पूर्ण ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को प्राप्त कर सकें तथा पेरिस समझौते में किये गये वायदे के अनुरूप 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हरित ऊर्जा से कर सकें। इससे हमारा व्यापार घाटा को कम होगा, विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे।

हमें अपने अनुसंधान केंद्रों में हमारी युवा पीढ़ी को उचित अवसर तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए अपनी मेधा और प्रज्ञा के आधार पर नई टेक्नोलॉजी द्वारा स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतियोगात्मकता को विश्व स्तर पर अपने कला कौशल द्वारा भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) द्वारा हमारे वैज्ञानिक अन्वेषणों की रक्षा करते हुए आगे बढना है। शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के अनुसार नई सोच और नये अन्वेषणों के लिये अटल नवाचार मिशन के तहत इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करके नये उत्पादों का निर्माण बढ़ा सकते हैं ताकि स्वदेशी तकनीक का विकास हो और आयात पर हमारी निर्भरता घटे। इससे हमारे रुपये की क्रय क्षमता बढ़ेगी जिससे रुपया डालर की तुलना में और मज़बूत हो। ज्ञात हो कि लगातार बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे की वजह से रुपया डालर की तुलना में कमजोर होता जा रहा है। अभी हाल ही में विदेशी निवेशकों के पूंजी बाज़ार से शेयरों की बिक्री करके डालर विदेशों में ले जाने से रुपये में बड़ी भारी गिरावट जारी है और अभी 87 रुपये के नज़दीक तक प्रति डालर का भाव चल रहा है। ट्रम्प 2.0 में जिस तरह की नीतियाँ अमेरिका अपना रहा है उससे लगता है भारत से आयातित वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ेगी जो भारत के निर्यात को आघात पहुँचाएगी। रुपये के कमजोर होने से भारत में आयातित तेल और महंगा होगा तथा इसका नकारात्मक असर हमारी महँगाई पर पड सकता है। भारत के लिये आवश्यक है कि स्वदेशी अर्थ नीति को दृढ़ता से अपनाये। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना तथा लघु उद्योगों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये और इसके लिये अनुसंधान का खर्च बढ़ना चाहिये ताकि हमारा 'ब्रेन ड्रेन' रुके और हम स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ायें। हमारे प्रवासी भारतीयों को देश में विनियोग करने के लिये किसी विशेष नीति द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो अपने आधुनिक विज्ञान, तकनीक तथा पूंजी लेकर भारत आयें। अभी तक वे ऋण के रूप में ही भारत में विदेशी मुद्रा भेजते हैं किंतु अगर वे भारत में उद्यमी के रूप में विनियोग करेंगे तो हमारे देश में स्वदेशी पूंजी और स्वदेशी तकनीक का विकास संभव होगा और विदेशी पूंजी के दबाव और प्रभाव से हम बच पाएंगे।

आज अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप, इजरायल ये सभी देश अपनी जीडीपी का 3–4 प्रतिशत अनुसंधान तथा वैज्ञानिक तकनीक के विकास पर खर्च करते हैं। भारत में भी तेजी से विकास तो हो रहा है किंतु पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में अभी हम 132वें स्थान पर हैं। साथ ही 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था वाले होकर भी हम दुनिया की कुल जीडीपी जो लगभग 105 ट्रिलियन अमरीकी डालर है उसका सिर्फ़ 3.5 प्रतिशत हिस्सा ही हैं, जहाँ अमेरिका 28.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर और चीन 19.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की जीडीपी के साथ 25 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दुनिया की जीडीपी का हिस्सा हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगभग एक तिहाई से ज़्यादा की कमाई सर्फ़ पेटेंट और ट्रेड मार्क, कापी राइट से आती है, जो भारत की कुल जीडीपी से दोगुनी है।

हमारे विकास का लक्ष्य उपभोक्तावादी संस्कृति नकारते हुए एक ऐसा वैकल्पिक आर्थिक दर्शन दुनिया के सामने रखना है जिससे प्रकृति का शोषण न हो, पर्यावरण संतुलित रहे। उत्पादन बढ़े और वितरण प्रणाली संतुलित हो ताकि समाज में समरसता बढ़े, वैषम्य घटे और व्यक्ति उद्यमी बने, स्वावलंबी बने। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन का आदर्श सामने रख कर चलें। अभ्युदय हमारा लक्ष्य होना चाहिये। राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के दिखाये मार्ग पर स्वदेशी को अपनायें तथा मज़दूरों और किसानों को उनकी उपज और श्रम का उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था करते हुए अर्थनीति के तीसरे विकल्प के द्वारा एक सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हो। ❑❑

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने से साकार होगा विकसित भारत का सपना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6 प्रतिशत के अनुमान और वित्त वर्ष 2024 की 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ से काफी कम है। इस आकलन के बाद आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ने के अंदेशा के बीच अब सबकी निगाहें एक फरवरी को आने वाले बजट पर लगी है कि सरकार अर्थव्यवस्था को को संजीवनी देने के लिए क्या कदम उठाती है।

भारत का शेयर बाजार भी आम बजट से आस लगाए बैठा हैं। पिछले दिनों अमेरिका में सत्ता परिवर्तन व अन्य वैश्विक घटनाओं के चलते शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशको ने अपना हाथ खींच लिया। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आधा से भी कम आया है, जिसके चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ सुस्त दिख रही है। हालांकि कई बार लगातार धड़ाम से नीचे आने के बावजूद भारत का शेयर बाजार फिर से उठ खड़ा हुआ और अब लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। वर्तमान में भी इसके और ऊपर चढ़ने के सकारात्मक संकेत हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में वित्तीय स्थिरता है। हमारी आईटी और एआई के क्षेत्र में दुनिया के पैमाने पर साख बनी हुई है। पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी आमदनी का स्तर सुदृढ़ है वहीं सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बुनियादी ढांचा के विकास में लगातार निवेश जारी रखने पर जोर दे रही है।

इन सब के बावजूद वर्ष 2025 में सेंसेक्स की दिशा बहुत हद तक जीडीपी के ग्रोथ पर ही निर्भर करेगी। मालूम हो कि वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही में हमारे विकास दर 8.01 प्रतिशत थी जो वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई। वर्ष

आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ने के अंदेशा के बीच अब सबकी निगाहें एक फरवरी को आने वाले बजट पर लगी है कि सरकार अर्थव्यवस्था को को संजीवनी देने के लिए क्या कदम उठाती है।

–अनिल तिवारी

2024–25 के अग्रिम अनुमान में इसके गिरकर 6.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया गया है। अगर यह गिरावट जारी रहती है तो हमारी कंपनियों का माल कम बिकेगा, उनके लाभ दबाव में आएंगे और शेयर बाजार निश्चित रूप से टूटेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्ष में भारत की विकास दर 6.01 प्रतिशत रहेगी। यदि विकास दर इससे अधिक रहती है तो हम मान सकते हैं कि हम अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि विकास दर 6.01 प्रतिशत से कम रही तो हमें मानना चाहिए कि हम अपेक्षा से कम विकास दर हासिल कर रहे हैं और यह शेयर बाजार के लिए हर हाल में नकारात्मक होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है तो कंपनियां अधिक लाभ कमाती हैं और शेयर बाजार उछलता इतराता रहता है।

भारत में भविष्य की विकास दर की दिशा का एक महत्वपूर्ण बिंदु अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी है। क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन करें। वह अमेरिका में होने वाले आयतों पर आयात–कर बढ़ाना चाहते हैं जिससे उनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। ट्रंप ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटना चाहते हैं। अमेरिका के प्रमुख व्यापारी एलन मस्क ने अभी हाल ही में अपनी बात रखाते हुए कहा है कि 'ग्लोबलाइजेशन इज ए कल्चरल सोसाइड' यानी उनकी नजर में अब वैश्वीकरण एक सांस्कृतिक आत्महत्या जैसा है। अगर ट्रंप का अमेरिकी प्रशासन वैश्वीकरण की नीति से पीछे भागता है और अमेरिका फर्स्ट की नीतियों को वास्तव में पूरी ताकत के साथ लागू करता है तो भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी उद्योगों की घर वापसी से भारत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वापस जाएगा। अमेरिका द्वारा आयात कर बढ़ने से भारत के लिए निर्यात करना कठिन हो जाएगा, उस स्थिति में भारत की निर्यातक कंपनियों के लाभ दबाव में आएंगे, जिसका सीधा असर हमारे उद्योगों पर और उसके बाद सकल घरेलू उत्पादन दर पर भी पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनाए रखने के लिए सरकार को मांग और निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि सरकार टैक्स में रियायत दे ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे। जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

इसी तरह भू–राजनीतिक तनाव का भी अर्थव्यवस्था के विकास पर सीधा असर पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल और हमास के बीच तनातनी, सीरिया और ताइवान में युद्धों की लगातार बढ़ती आशंका के कारण भी व्यापार की रफ्तार धीमी हो सकती है।

इसी तरह जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी प्रमुख है। आज वैश्विक स्तर पर सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। भारत में अगर सूखा पड़ जाए अथवा अति वृष्टि हो जाए तो धान और गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए उत्पादन कम होते ही यहां के ग्रामीण निवासियों की क्रय शक्ति घट जाती है।

एनएसओ का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग और निवेश घटने से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ने जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर के बीच कैपिटल एक्सपेंडिचर में 12.3 प्रतिशत की सालाना गिरावट आई। लोकसभा चुनाव और फिर भारी बारिश की वजह से सरकार यह पैसा बुनियादी ढांचा विकास पर खर्च नहीं कर पाई, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बना। वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में इसमें तेजी आने की आशा है, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सकता है।

एनएसओ के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ अच्छी रहेगी और निजी खपत में भी अच्छा सुधार दिखेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट के कारण स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। वहीं, कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से ग्रामीण मांग में रिकवरी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मांग कमजोर है। देखना होगा कि शहरी मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में क्या उपाय करती है?

अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनाए रखने के लिए सरकार को मांग और निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि सरकार टैक्स में रियायत दे ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे। जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

अगर फरवरी की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है तो उससे भी शहरी उपभोक्ता वर्ग को कम ईएमआई के रूप में राहत मिलेगी। इससे जो बचत होगी, उससे भी मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्याज दरें कम होती हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर की दिलचस्पी भी निवेश में बढ़ती है। वह अपनी क्षमता बढ़ाता है, जिससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं, लिहाजा मांग मजबूत होती है। अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करनी होगी। ❑❑

प्रजातंत्र और जन भागीदारी

26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना भारत तमाम उपलब्धियां हासिल कर चुका है। कई एक मोर्चे पर अनुकरणीय और अनूठी नजीर पेश करते हुए हमारा देश आश्वस्त करता है कि यहां लोकतंत्र की मशाल प्रशस्त रहेगी। हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि विश्व का पहला गणतंत्र भारत में ही वैशाली में उदित हुआ था। हमारी विरासत में है आम जन की भलाई का सरोकार। गणतंत्र ने हमें मजबूती दी है और हम गणतंत्र से निरंतर मजबूत से मजबूत हुए हैं।

बीते साल 2024 के मार्च महीने में देश के प्रधानमंत्री ने प्रजातंत्र में जन भागीदारी की वकालत करते हुए देश के आम नागरिकों को एक खुला पत्र लिखा था।अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि भारत व्यापक विविधताओं वाला देश है जिसमें विभिन्न लोगों के विचारों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उच्च विकेंद्रीकृत संघीय ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सत्ता दिल्ली और राज्य की राजधानियों में केंद्रित हैं। उनका मानना है कि सत्ता का स्वाभाविक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार और पार्टी वृहद विकेंद्रीकरण के पक्ष में खड़ी है। जनसत्ता के व्यापक संग्रह को अब तक वास्तविक अर्थ में परखा ही नहीं गया है। हम शासन में लोगों को कार्यकारी और सहायक के रूप में शामिल करने में सक्षम नहीं हुए हैं। उनका मानना है कि केंद्र से राज्य तक देश में एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा बने तथा उसमें जनता की आवाज प्रमुख हो इसके लिए बहुफलकीय परिवर्तन जरूरी है।

भारतीय गणतंत्र के 76 साल पूरे हो गए। इन साढ़े सात दशकों में बतौर राष्ट्र भारत ने लंबा सफर तय किया है। इस सफर में उतार–चढ़ाव हैं, कामयाबियां हैं, लगातार परेशान करने वाली समस्याएं हैं और भविष्य की चुनौतियां हैं। इन सबके बीच भारत के कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी भारत में लोकतांत्रिक ढांचे का बना रहना है। यह इसलिए भी है अहम है क्योंकि पड़ोसी देशों में लगातार फौजी हुकूमत का बोल बाला रहा है। चाहे वह पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश। शांति और स्थायित्व का भरोसा यहां है। लोकतंत्र के इस सफर में भारतीय राजनीति में एक और अहम बदलाव देखने को मिला हैं। दो दशक पहले तक देश में एक ही राजनीतिक दल का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब देश ही नहीं, राज्य स्तर पर, भी गठबंधन की राजनीति का चलन है। सही मायनों में यह चलन कम, जरूरत ज्यादा है। अब आम मतदाताओं पर किसी एक राजनीतिक दल का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रह गया है। बहुत लोग है जो गठबंधन की राजनीति को लोकतंत्र के लिए उपयोगी नहीं मानते लेकिन मेरे ख्याल से मजबूत लोकतंत्र की आधारभूत बुनियाद यही है कि कोई सरकार या फिर कोई राजनीतिक दल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो। नहीं तो ऐसी सरकारें और राजनीतिक दल मनमानी पर उतर आते हैं। इस लिहाज से लोकतंत्र में पार्टियां जितनी कमजोर होंगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोकतांत्रिक पार्टियों के बिना लोकतंत्र रह सकता है, होना यह चाहिए कि बराबरी वाली ताकत के दल और गठबंधन मौजूद हों।

भारत के कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी भारत में लोकतांत्रिक ढांचे का बना रहना है। यह इसलिए भी है अहम है क्योंकि पड़ोसी देशों में लगातार फौजी हुकूमत का बोल बाला रहा है। चाहे वह पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश।

–शिवनंदन लाल

लोकतंत्र के अलावा देश की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी इसका आर्थिक मोर्चों पर कामयाब होना रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तब दुनिया में इसकी गिनती गरीब देश

के रूप में थी। इस लंबे सफर में आम भारतीय की आमदनी बढ़ी है। गरीबी कम हुई है, हालांकि यह उतनी कम नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए लेकिन जिस सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर को विकास का पैमाना माना जाता है, उसमें मौजूदा आर्थिक मंदी के दौर में भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां विकास के आंकड़े ऊपर की ओर है। भारत की आर्थिक बुनियाद का ढांचा अंदरूनी ग्रोथ है। इसमें स्थिरता का भाव ज्यादा है। यही वजह है कि जब दुनिया की तमाम आर्थिक ताकतें चरमराती दिखीं, तमाम आशंकाओं के बावजूद भारतीय जीडीपी की विकास दर बहुत कम नहीं हुई।

भारत का आर्थिक बाजार बाहरी ताकतों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। चीन की तरह यहां कोई एक्सपोर्ट इकॉनामी नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान भारतीय बाजार की ओर गया है। भारी संख्या में लोग यहां निवेश करने को उतावले हैं।

मालूम हो कि तीन दशक पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में भारत को अपना रिजर्व सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। यह कदम भी भारतीय गणतंत्र के सबसे अहम पड़ावों में एक रहा। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में रोजगार के विकल्प बढ़े। लोगों की आमदनी बढ़ी। पैसा बढ़ने से लोगों के जीवन में खुशहाली का प्रवेश हुआ। बेहतर जीवन शैली और पैसों की आमद ने भारत में एक नए 'ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास' को तैयार किया। इस मिडिल क्लास में कुछ भी कर दिखाने का, कुछ हासिल करने का भरोसा है, यही वजह है कि दुनिया भर में भारतीय लोगों ने बड़ी तेजी से अपनी प्रतिभा और कौशल के बूते जगह बनाई है। दुनिया भर के लोगों का भारत और भारतीय लोगों के प्रति नजरिया बदला है। दुनिया के लोग अब भारत के लोगों को कहीं ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं।

इन चमकदार कामयाबियों के साथ–साथ कुछ समस्याएं अब भी मौजूद हैं। मसलन देश भर में नागरिक सुविधाओं को अब भी काफी अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका है। हालांकि हैजा, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियां कम हो गई है, बावजूद इसके देश के हर नागरिक तक स्वाथ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं हो पाई है। देश के एक बहुत बड़े तबके तक सड़क, बिजली और पानी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा देश के अंदर नक्सलवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता जैसे मसले भी हैं।

भारत को अपने पड़ोसी देशों से समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि दुनिया के स्तर पर भारत इन दिनों मजबूत हुआ है। अमेरिका–चीन जैसे मजबूत देश भी इस बात को भली भांति स्वीकार कर रहे हैं।

आज देश की अर्थव्यवस्था नेहरूवादी–समाजवाद का खोल उतारकर निजी देशी– विदेशी पूंजी के नेतृत्व में सरपट दौड़ रही है। सबसे तेज गति, खूब समृद्धि भी। फोर्ब्स' पत्रिका के मुताबिक डालर अरबपतियों की सूची में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। यही नहीं, भारतीय 'डॉलर अरबपतियों' की कुल संपदा चीनी अरबपतियों की संपदा से काफी अधिक है। इस मायने में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में संपदा बरस रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस 'गण' की सेवा के लिए भारत गणतंत्र बना, उस 'गण' को तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था से बहुत कम मिला। खुद सरकारी आंकड़े इस तथ्य की गवाही देते हैं।

सवाल है कि अर्थव्यवस्था से निकल रही जबर्दस्त समृद्धि कहां जा रही है? निश्चय ही इस सवाल का एक सिरा देश में डालर अरबपतियों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि से से जुड़ता है। जाहिर है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है कि डॉलर अरबपति देश की कुल जनसंख्या के मात्र 0.00001 प्रतिशत हैं लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक चौथाई हिस्से पर उनका कब्जा है। दूसरी ओर, खुद सरकार पिछले कई वर्षों से 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज देकर जिंदा रखे हुए हैं। आबादी का 78 प्रतिशत हिस्सा प्रतिदिन कम आय पर गुजर कर रहा है। साफ है कि देश में गैर बराबरी बढ़ रही है। सच पूछिए तो आज गरीबी से कहीं अधिक आर्थिक विषमता और गैर बराबरी भारतीय गणतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यह गैर बराबरी कई रूपों में उभरकर हमारे सामने आ रही है। इसका एक रूप तो मौजूदा महा महंगाई में भी देखा जा सकता है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि गणतंत्र बनने के बाद देश ने अन्न उत्पादन में बहुत तरक्की की है लेकिन

प्रति व्यक्ति/प्रति दिन खाद्यान्न की उपलब्धता लगातार कम हुई है?

हालांकि कई लोगों का मानना है कि आर्थिक समृद्धि के साथ लोगों ने अनाजों के बजाय अंडे–मांस–दूध और सब्जियां अधिक खाना शुरू कर दिया है। इस दावे में थोड़ी सच्चाई है लेकिन कम आय पर गुजर–बसर करने वाले कोई 80 करोड़ लोगों के लिए सच यही है उन्हें हर दिन दोनों जून दाल–रोटी के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। गांवों में लगभग 65 करोड़ लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। इस आबादी का लगभग 50 प्रतिशत तो खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है। जिन सामान्य लोगों को दो वक्त की रोटी, रहने को घर, पढ़ने को विद्यालय, इलाज के लिए अस्पताल न हो उनके लिए जनतंत्र कैसा?जनतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें 5 साल की अवधि में एक बार देश के निवासियों को मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्वाचन समाप्त होते ही चुने गए प्रतिनिधि शासक बन जाते हैं और सामान्य जन के अधिकारों को अपने हाथ में ले लेते हैं।

प्रजातंत्र की सबसे प्रासंगिक परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। उनके अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। अर्थात लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। क्या व्यवहार में ऐसा है, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा, नहीं।

आज समाज में प्रजातंत्र की परिकल्पना उसी तरह की जा रही है जैसे एक पुरानी कथा में कई नेत्रहीनों ने हाथी की कल्पना की थी। इससे भी आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार द्वारा देश की रक्षा और राजनीतिक महत्व के स्पेक्ट्रम को स्वार्थ बस निजी कंपनी को बेचने का उदाहरण भी मौजूद है, जिसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मानते हुए निरस्त किया। अगर आपको याद हो तो जिओ नेटवर्क की शुरुआत मुफ्त कनेक्शन और सर्विस उपलब्ध कराने से हुई तब सभी मोबाइल ऑपरेटरों ने सवाल उठाए और सबने सरकार से आग्रह किया कि इस सेवा प्रदाता को अनैतिक प्रतिस्पर्धा से रोका जाना चाहिए लेकिन चुनी हुई सरकार ने नहीं रोका और उसका परिणाम तमाम मोबाइल कंपनियों के बंद होने के रूप में निकला। बाद में बची–खुची कंपनियों को बचाने के लिए खुद सरकार को आगे आना पड़ा। भारतीय संविधान के अंगीकरण के मौके पर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था संविधान अच्छा है या बुरा यह संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति की मानसिकता यदि लोकतांत्रिक नहीं होगी तो उसकी परिणिति 1975 के आपातकाल की तरह हो सकती है। दोष पूर्ण लोकतंत्र के अनेक उदाहरण के बीच भारत ने तरक्की की है। जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 साल हो गई है। साक्षरता दर 77 प्रतिशत पहुंच गई है। देश मंगल ग्रह तक पहुंचा है। अनेक वैज्ञानिक खोजें लगातार आगे बढ़ रही हैं,लेकिन जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर है जहां हम बहुत पीछे हैं। देश में मीडिया की स्वतंत्रता 142वें स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां है। जिन 55 देशों को दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देश में शामिल किया गया है उनमें भारत भी शामिल है। लोक प्रजातंत्र का सही मायने में अर्थ लोगों की भागीदारी है, यानी जनता की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उस देश का प्रजातंत्र उतना ही फलेगा फूलेगा। हमारे देश में जनता की भागीदारी महज चुनाव तक सीमित है। राजनीतिक दलों ने भारत को सांप्रदायिक जाति और क्षेत्रवाद के दलदल में डाल दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के कारण हमारे देश में विधायकों और सांसदों का दल–बदल करना, सरकारों का गिरना, निर्धारित समय से पहले चुनाव होना, उपचुनाव होना, लोकतंत्र के विश्वास को कमजोर करता है। संसद और विधानसभा में बैठकों की संख्या लगातार घट रही है। सदन अखाड़ा बनते जा रहे हैं। कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। मौका मिलते ही सत्ताधारी दल विरोधी दलों को सदन से बाहर कर जनता के नाम पर विधेयक पास कर लेते हैं।

यही कारण है कि तरक्की की तेज रफ्तार के बावजूद हमारे गणतंत्र का 'गण' कहीं पीछे छूटता जा रहा है। वह अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। यही नहीं, कहीं न कहीं उसे यह भी लगने लगा है कि अर्थव्यवस्था के कर्ता–धर्ताओं को उसकी परवाह नहीं रह गई है। आखिर 'गण' को नजरअंदाज करके गणतंत्र कैसे आगे बढ़ सकता है?

हमारा मानना है कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह दोषरहित नहीं हो सकती। देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन आवश्यक होता है। हमारा संविधान हो या प्रशासन या चुनाव सभी को वक्त की चुनौतियों से पार पाने के लिए सुधार की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण है राष्ट्र के संचालन और आवश्यक संशोधन में पारदर्शिता जवाबदेही और कर्तव्य का निर्वहन हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा कर्त्तव्यों से विमुख हो जाना गण का तंत्र से और तंत्र का गण से दूर हो जाने की वजह बना है। इसीलिए गणतंत्र बन जाने के लंबे अरसे के बाद भी तंत्र की ओर आशा भरी निगाह से गण निहार रहा है कि खुशहाली आए। ❑❑

ताकि बरकरार रहे शिक्षा और शिक्षक की गुणवत्ता!

सेवा नहीं, ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान आसान रास्तों से अर्जित नहीं होता। ज्ञान साधना है। शिक्षण कला भी है, जो हर ज्ञानी के पास भी नहीं होता। हर डिग्रीधारी उच्च शिक्षा प्रदान करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक की नियुक्ति में चूक करना, समाज को कमजोर करना है। शिक्षा और शिक्षक की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बरकरार रहनी चाहिए।

–डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय, विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया है, जिसमें नियुक्ति के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप इसका उद्देश्य अकादमिक मानकों को मजबूती प्रदान करना और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है, जिससे उच्च शिक्षा के हर पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाई जा सके। मसौदा अभी सुधार और परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब कोई भी छात्र, जिसके चार साल के स्नातक में 75 प्रतिशत मार्क्स हों, पीएचडी में दाखिला ले सकता है, और पीएचडी के उपरांत वह सहायक शिक्षक नियुक्त होने के योग्य है। यही नहीं, अगर उसके स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री पीएचडी के विषय से भिन्न भी है, तो जिस विषय में उसने पीएचडी की हो, उस विषय के शिक्षक के रूप में वह नियुक्त हो सकता है यानी अब नेट अनिवार्य नहीं है, और जिस उम्मीदवार के स्नातक या स्नातकोत्तर के विषय उसके नेट परीक्षा के विषय से अलग भी हों तो जिस विषय में उसने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह उस विषय में शिक्षक बनने योग्य है। अगर किसी उम्मीदवार ने किसी हो तो वैसे लोग भी सहायक शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेट या पीएचडी को ही मानक मान लिया गया है, और आप किस विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट–ग्रेजुएशन करते हैं, उसे अप्रासंगिक कर दिया गया है। यूं तो यह नियम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उसमें समावेशिता और लचीलापन लाने के उद्देश्य से किया गया है, पर इससे संदेश निकल कर आता है कि आपके कॉलेज की पढ़ाई का आपके ज्ञानवर्धन या आपको किसी विषय में दक्ष बनाने में कोई योगदान नहीं है, या वह जरूरी नहीं है। क्या सालों महाविद्यालय की उच्चस्तरीय शिक्षा के कोई मायने नहीं हैं? क्या सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा पास करके कोई किसी विषय की बारीकियों का ज्ञाता हो सकता है? या जिस विषय में आपका शैक्षणिक आधार न हो, उसमें आप अच्छा शोध कर सकते हैं? और बिना उस विषय के गहन अध्ययन के आप शिक्षा प्रदान करने के काबिल हो सकते हैं? सालों किसी विषय के सान्निध्य में रहने के बाद कोई विषय विशेषज्ञ बन पाता है। जब नेट परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो गई थी तब भी सवाल उठे थे कि मानविकी के विषय की गूढ़ता की जांच या भाषा और साहित्य की दक्षता ऑब्जेक्टिव परीक्षा के जरिए कैसे स्थापित की जा सकती है? और अब सिर्फ इस परीक्षा के आधार पर शिक्षक का चयन करना कितना उचित होगा!

एक और बात जो इस मसौदे से स्थापित होती है, वह यह है कि इसमें नियुक्तियों में सिलेक्शन कमिटी को सशक्त कर दिया गया है, जिसके अपने खामियाजे हो सकते हैं। हम देख रहे हैं, देश भर में कितने नियुक्ति घोटाले और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक चयन समिति के हाथों पूरी चयन प्रक्रिया का निष्कर्ष

छोड़ना, निष्पक्षता के नियमों पर खरा नहीं उतरता। खासकर विषय विशेष में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उम्मीदवारों का चयन सिर्फ चयन समिति पर छोड़ देना पक्षपात और अपारदर्शिता को न्योता देने के बराबर है। पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन विषयों में कितनी सीटें विशिष्ट योगदान वालों को दी जा सकती हैं, और उनके मानदंड तय होने चाहिए, और इस तरह की नियुक्तियां कुछ चुने हुए कोर्सेज में ही होनी चाहिए जिनमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की जरूरत हो सकती है, पर यह प्रावधान हर विषय और हर अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए होना थोड़ा गैर–जरूरी लगता है खासकर तब जब कई क्वालिफाइड उम्मीदवार अभी भी नौकरी की आस देख रहे हों।

देश में सरकारी नौकरियों के प्रति इतना रुझान है और पद इतने कम कि फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। किसी महाविद्यालय में सहायक शिक्षक की नौकरी ग्रेड एक लेवल की नौकरी है और आईएएस अधिकारियों का भी यही ग्रेड होता है।

जब एक अधिकारी बनने की प्रक्रिया मुश्किल होती है, और उम्मीदवारों को परीक्षा के कई चरणों से गुजरना होता है, तो सहायक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ सिलेक्शन कमिटी पर क्यों छोड़ दी जाती है, जहां प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा हो वहां पारदर्शिता और निष्पक्षता कायम रखने के लिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना जरूरी है, और चयन समितियां व्यक्तिपरक होती हैं। जैसा कि राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं में होता है, उम्मीदवारों की योग्यता के ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन पर ज्यादा तरजीह दी जाती है और इंटरव्यू या सिलेक्शन बोर्ड के अंक कम होते हैं। वैसे ही कैंडिडेट के पर्सनल क्रेडेंशियल को महत्व मिलना चाहिए और साक्षात्कार औपचारिकता होनी चाहिए उसके व्यक्तित्व के आकलन के लिए जिसके अंक पूरक होने चाहिए, संपूर्ण आधार नहीं।

देश में सरकारी नौकरियों के प्रति इतना रुझान है और पद इतने कम कि फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। किसी महाविद्यालय में सहायक शिक्षक की नौकरी ग्रेड एक लेवल की नौकरी है और आईएएस अधिकारियों का भी यही ग्रेड होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत वैसे भी कॉलेज के डिग्री कोर्सेज में मुख्य विषय (कोर पेपर्स) कम कर दिए गए हैं, जहां छात्र पढ़ तो 8 पेपर रहा है पर उसके चुने हुए कोर्स के पेपर तीन ही हैं, और उसमें भी उनकी क्रेडिट संख्या 5+3 से 3+1 हो गई है, और बहुविषयी पेपर्स ज्यादा हैं यानी पहले की तुलना में अब कॉलेज छात्रों की अपने विषय की टीचिंग–लर्निंग अवधि कम हो गई है, तो जाहिर है कि उन्हें अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने के कम घंटे मिल रहे हैं, जिससे सब्जेक्ट नॉलेज की कमी हुई है, और शिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ा है, और कई शिक्षक समूहों ने क्रेडिट आवर्स बढ़ाने की मांग की है। अब शिक्षक नियुक्ति में भी कॉलेज की पढ़ाई को दरकिनार कर दिया जाए तो प्रश्न चिह्न शिक्षक की दक्षता पर ही लग जाएगा।

यही नहीं, अगर किसी भी अकादमिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति कोई भी विषय पढ़ाने के योग्य सिर्फ पीएचडी या नेट परीक्षा के आधार पर हो जाए, तो शिक्षा की क्या विश्वसनीयता रह जाएगी।

इससे महाविद्यालयों के विषय विशेष के शिक्षक पदों की संख्या पर भी असर पड़ेगा। जिस शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की जा रही है, वह विशेषज्ञता के पैमाने को ढीला कर के नहीं पाई जा सकती। लचीलापन छात्रों के दिए जाने वाले विकल्पों में बेशक, होना चाहिए पर उनकी दक्षता के पैमानों पर नहीं। एनईपी का बहुविषयी दृष्टिकोण सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा है पर इसे फलीभूत करने की कोशिश में विशेषज्ञता के महत्त्व को नहीं नकारा जा सकता। शिक्षण की गुणवत्ता क्षीण न हो इसके लिए, अकादमिक पृष्ठभूमि को तरजीह देना जरूरी है, और इस गुणवत्ता की परख ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता कायम रखी जा सके और पक्षपात के अवसर कम हों।

हालांकि अभी ये नियुक्ति के नियम–निर्देश प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं, और शिक्षक समुदाय अपने विचार और सुझाव मंत्रालय को भेज 'सकते हैं। उम्मीद है कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और सभी बिंदुओं से शिक्षण जगत की चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा जिससे दुरुस्त शिक्षा नीति कार्यान्वित की जा सके। याद रहे कि शिक्षण मात्र पेशा नहीं है, अन्य रोजगारों की तरह सिर्फ नौकरी नहीं है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, चिंतक होता है, प्रेरणा– स्त्रोत होता है। सेवा नहीं, ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान आसान रास्तों से अर्जित नहीं होता। ज्ञान साधना है। शिक्षण कला भी है, जो हर ज्ञानी के पास भी नहीं होता। हर डिग्रीधारी उच्च शिक्षा प्रदान करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक की नियुक्ति में चूक करना, समाज को कमजोर करना है। शिक्षा और शिक्षक की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बरकरार रहनी चाहिए।❑❑

वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में
मध्यमवर्गीय परिवारों को देनी होगी राहत

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मध्यमवर्गीय परिवारों की प्रमुख भूमिका रहती है। देश में ही निर्मित होने वाले विभिन्न उत्पादों की मांग इन्हीं परिवारों के माध्यम से निर्मित होती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार जब मध्यमवर्गीय परिवारों की श्रेणी में शामिल होते हैं तो उन्हें नया स्कूटर, नया फ्रिज, नया एयर कंडिशनर, नया टीवी एवं इसी प्रकार के कई नए पदार्थों (उत्पादों) की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही, नए मकानों की मांग भी मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच से ही निर्मित होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उस देश का आर्थिक विकास भी उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत में भी हाल ही के वर्षों में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। परंतु, मुद्रा स्फीति, कर का बोझ एवं इन परिवारों की आय में वृद्धि दर में आ रही कमी के चलते इन परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे कई कम्पनियों का यह आंकलन सामने आया है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग में कमी दृष्टिगोचर हुई है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली कम्पनियों का इस संदर्भ में आंकलन बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय तिमाही में इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री एवं लाभप्रदता में भी कमी दिखाई दी है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ अब सीधे ही इन परिवारों को पहुंचने लगा है। 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रतिमाह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों के खातों में सहायता राशि सीधे ही जमा की जा रही है। विभिन्न राज्यों द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहिना योजना आदि माध्यम से

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट के माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए।

–प्रहलाद सबनानी

महिलाओं के खातों में सीधे ही राशि जमा की जा रही है। इसके साथ ही इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होने लगे हैं। जिससे इस श्रेणी के परिवारों में से कई परिवार अब मध्यमवर्गीय श्रेणी के परिवारों में शामिल हो रहे हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री ने हाल ही में भारतीय संसद को बताया है कि देश में पिछले 10 वर्षों में रोजगार उपलब्ध नागरिकों की संख्या 36 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 64.33 करोड़ के स्तर पर आ गई है, यह संख्या वर्ष 2014–15 में 47.15 करोड़ के स्तर पर थी। वर्ष 2024 से वर्ष 2014 के बीच, 10 वर्षों में रोजगार में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी अर्थात इस दौरान केवल 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हो सकीं थी, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच 17.19 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं, यह लगभग 6 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। पिछले केवल एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24 के बीच ही देश में लगभग 4.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच कृषि के क्षेत्र में रोजगार में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार विनिर्माण के क्षेत्र में भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच रोजगार में केवल 6 प्रतिशत दर्ज हुई थी जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। सेवा के क्षेत्र में तो और भी अधिक तेज वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच सेवा के क्षेत्र में रोजगार 25 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सबका असर बेरोजगारी की दर में कमी के रूप में देखने में आया है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017–18 के 6 प्रतिशत से वर्ष 2023–24 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा असर कामकाजी आबादी अनुपात पर भी पड़ा है जो वर्ष 2017–18 के 46.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 58.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सबसे अच्छी स्थिति तो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे नागरिकों की संख्या में वृद्धि से बनी है। क्योंकि संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं को नियोक्ताओं द्वारा कई प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। संगठित क्षेत्र में शामिल होने वाले युवाओं (18 से 28 वर्ष के बीच की आयु के) की संख्या में सितम्बर 2017 से सितम्बर 2024 के बीच 4.7 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है, ये युवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) से भी जुड़े हैं।

यदि किसी देश में मुद्रास्फीति की दर लगातार लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहे एवं नागरिकों की आय में वृद्धि दर मुद्रास्फीति में हो रही वृद्धि दर से कम रहे, तो इसका सीधा असर मध्यमवर्गीय परिवार के बचत एवं खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है। यदि मध्यमवर्गीय परिवार के खर्च करने की क्षमता कम होगी तो निश्चित ही बाजार में विभिन्न उत्पादों की मांग भी कम होगी, इससे विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी कम होगी।

यदि किसी देश में मुद्रा स्फीति की दर लगातार लम्बे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहे एवं नागरिकों की आय में वृद्धि दर मुद्रास्फीति में हो रही वृद्धि दर से कम रहे तो इसका सीधा असर मध्यमवर्गीय परिवार के बचत एवं खर्च करने की क्षमता पर पड़ता है। यदि मध्यमवर्गीय परिवार के खर्च करने की क्षमता कम होगी तो निश्चित ही बाजार में विभिन्न उत्पादों की मांग भी कम होगी इससे विभिन्न कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी कम होगी। यह स्थिति हाल ही के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर है। अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे जिससे मुद्रा स्फीति की दर देश में कम बनी रहे एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आय में वृद्धि हो। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों की आय पर लगाए जाने वाले आय कर में भी कमी की जानी चाहिए। बैकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा द्वारा भी मध्यमवर्गीय परिवारों को कुछ हद्द तक राहत पहुंचाई जा सकती है। ऋण पर ब्याज दरों में कमी करने से मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा ऋण खातों में जमा की जाने वाली मासिक किस्त की राशि में कमी होती है और उनकी खर्च करने की क्षमता में कुछ हद्द तक सुधार होता है।

मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में यदि उक्त उपाय नहीं किया जाते हैं तो बहुत सम्भव है कि यह मध्यमवर्गीय परिवार एक बार पुनः कहीं गरीबी रेखा के नीचे नहीं खिसक जाये। अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट के माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर)

भूजल स्तर में गिरावट और गुणवत्ता का सवाल

भूजल के स्तर में तेजी से गिरावट व भूजल की गुणवत्ता जहां बड़े खतरे के संकेत हैं, वहीं साफ पेयजल की कमी के भीषण संकट की चेतावनी है। खासकर इसलिए कि धरती पर केवल तीन फीसदी ही मीठा पानी है जो हर जीव को जीवन दान देता है। दरअसल, धरती, समुद्र, उसके खारे पानी और धरती पर उपलब्ध मीठे पानी का निकट का रिश्ता है। जब हम धरती के आकार और उसकी जैव विविधता खासकर पेड़–पौधों से छेड़छाड़ करते है तो बारिश, जल प्रबंधन एवं जल उपलब्धता आदि पर व्यापक असर पड़ता है। भूजल भी इससे अछूता नहीं। भूजल का बढ़ता संकट यानी उसके भयावह स्तर तक गिरने का अहम कारण उसका बेतहाशा दोहन है जिसके चलते जमीन की भीतरी परत दिनोंदिन तेजी से सिकुड़ रही है। नतीजतन जमीन के धंसने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं इससे भूमि की भीतरी परत (एक्वीफायर) की जलधारण क्षमता खत्म हो जाती है।

भारत में संभावित भूजल भंडार 432 लाख हैक्टर मीटर और दोहन योग्य सकल भूजल की मात्रा 396 लाख हैक्टर मीटर है। इस विशाल मात्रा का विकास, बरसाती पानी के, एक्वीफायर में रिसने के कारण होता है। यही पानी प्राकृतिक जल चक्र का अभिन्न अंग है। बारिश के दिनों में हर साल यह पुनर्जीवित होता है। अतः भूजल का दोहन, उसके अविरल प्रवाह तथा अवांछित घटकों के सुरक्षित निष्पादन को समझकर करना बेहद जरूरी है। वर्ष 1960 के बाद से पानी की मांग दोगुनी से अधिक हो गयी है। भूजल दोहन के मामले में हमारा देश शीर्ष पर है। देश का उत्तरी गांगेय इलाका तो भूजल दोहन के मामले में देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले कीर्तिमान बना चुका है। राजधानी दिल्ली सहित समीप के कई शहरों का डार्क जोन में आना और दिल्ली एनसीआर में गंभीर पानी का संकट इसका सबूत है। नतीजतन, इस इलाके की जमीन की सतह का आकार तेजी से बदल रहा है। यहां धरती

सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में आंध्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भूजल के 12.5 फीसदी नमूने उच्च सोडियम की मौजूदगी के कारण सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं पाये गये हैं। देश के 440 जिलों के भूजल में बढ़ा नाइट्रेट स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहा है।

–स्वदेशी संवाद

भी तेजी से धंसने लगी है। यह सिलसिला केवल एनसीआर तक ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक जारी है। पंजाब के 23 जिलों में भूजल 'की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। दरअसल पंजाब की 94 फीसदी आबादी पीने के पानी के लिए भूजल पर ही निर्भर है। भूजल में बढ़ते प्रदूषण का यहां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

बीते दो दशकों में सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ है जिससे जहां भूजल की मांग बढ़ी वहीं गुणवत्ता खराब होती चली गयी। यहां भूजल में भारी धातुओं और रेडियो एक्टिव पदार्थों की मौजूदगी में तेजी से इजाफा हुआ। इसी प्रकार हरियाणा के 141 विकास खंडों में से 85 भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते गंभीर स्थिति में हैं। यह हिस्सा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 60 फीसदी है। इससे राज्य की भूजल संकट की स्थिति का अंदाजा लग सकता है। गौरतलब यह है कि देश में भूजल निकासी का औसत 63 फीसदी है जबकि हरियाणा में भूजल निकासी 137 फीसदी से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग ने दस महानगरों को अति दोहित की श्रेणी में रखा है और जल के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमावली भी बनाई है। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। लेकिन यह नियमावली मात्र खानापूर्ति ही रह गयी है। वैज्ञानिक जलवायु में आ रहे बदलाव में भूजल दोहन की बड़ी भूमिका मानते है। ऐसे में भूजल प्रबंधन और भूजल उपयोग सम्बंधी रणनीतियों में व्यापक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्योंकि आबादी में बढ़ोतरी, बढ़ता शहरीकरण और कृषि भूमि पर गहन खेती के साथ ही लगातार भूजल की गिरावट हालात को और भयावह बना देगी।

कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के मैदानों तक भूमि के व्यापक हिस्से में भूजल की बड़े पैमाने पर कमी हुयी है। वहीं आर्सेनिक, नाइट्रेट, सोडियम, यूरेनियम, फ्लोराइड आदि की अधिकता के कारण भूजल की खराब गुणवत्ता की चिंता केवल साफ पेयजल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सिंचाई के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। आंध्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भूजल के 12.5 फीसदी नमूने उच्च सोडियम की मौजूदगी के कारण सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं पाये गये हैं। देश के 440 जिलों के भूजल में बढ़ा नाइट्रेट स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहा है। सीजीडब्लयूबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पानी में नाइट्रेट प्रदूषण मुख्यतः नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों और पशु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण होता है। एक रिपोर्ट की मानें तो पानी के 9.04 फीसदी नमूनों में फ्लोराइड का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक और 3.55 फीसदी आर्सेनिक की मौजूदगी पायी गयी। यह प्रदूषण पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर, किडनी, हड्डियों और त्वचा रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

सिंचाई के भी उपयुक्त ना माने जाने वाले भूजल का प्रतिशत एक साल में 7.69 से बढ़कर 8.07 तक बढ़ गया है। पानी में लवणों की मौजूदगी लगातार बढ़ते जाना नाकामी ही है। जमीन पर सोडियम की परत जमना भी अच्छा संकेत नहीं है। जहां सोडियम की मात्रा सीमा से अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाने के साथ प्रभावी निगरानी भी जरूरी है। देश में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट के लिए उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार की व्यवस्था न होना, खेती में अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल, शहरीकरण, घरेलू कचरा मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इन पर अंकुश लगाये बिना भूजल की गुणवत्ता हासिल कर पाना टेढ़ी खीर है। ❑❑

(विजय गर्ग की कलम से)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2025–26 का बजट निकट भविष्य में संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मीडिया में कुछ समय से रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता पर विश्लेषण, समाचार और लेख प्रकाशित हो रहे हैं। भारत की सामरिक सुरक्षा को लेकर जनमानस में बहुत चिंता है क्योंकि हमारा देश चीन और चीन समर्थित पाकिस्तान से उत्तर, पूर्व से पश्चिम तक घिरा है जिनका युद्धोन्माद और भारत पर आक्रामकता से सभी परिचित हैं। चीन की आक्रामकता और हिंद महासागर में उसका विस्तारवाद एवं संरक्षणवाद भारत के अहित में है। भारत के काश्मीर और लद्दाख के अवैध कब्जे में चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर और काराकोरम हाइवे चीन को सेंट्रल एशिया में बढ़त दिलाता है भूमध्य सागर और युरोप तक चीन को सामरिक रूप से प्रभावशाली बनाता है। इस विषय पर बेबाक चर्चा आवश्यक है और वस्तुस्थिति को धरातल पर समझने और उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बजट को अर्थव्यवस्था के गुणा–भाग और आयकर दरों, छूट और जीएसटी के मीडिया में चर्चा से ऊपर उठकर देश की अभेद्य सुरक्षा को जनमानस की संवेदनशीलता से जोड़ने की आवश्यकता है।

अभी 8 जनवरी 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि वायु सेना प्रमुख चीफ मार्शल एन.पी. सिंह ने भारतीय वायुसेना में शोध, आधुनिकतम रक्षा प्रणाली के उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर देश को चेताया है। चीन ने अभी हाल में ही दो नये छठे जेनेरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट के लांच ने विश्व भर में गहरी चिंता व्याप्त कर दी है। जबकि भारत चौथी जेनेरेशन के तेजस मार्क– 1ए फाइटर जेट के जीई–एफ 404 टर्बोफैन जेट इंजन के लिए अमेरिका से आयात पर निर्भर हैं और स्वयं अमेरिका पांचवीं जेनेरेशन के फाइटर जेट के लिए अनुसंधान के स्तर पर ही सीमित है। वायु सेना प्रमुख ने तेजस के लिए अमेरिका से इंजन आपूर्ति पर देरी के गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारी वायु सेना को 180

देश की सुरक्षा की वृहद दृष्टि सरकार के सामने है और गंभीर चुनौतियां भी। इस वर्ष के बजट में रक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम दोगुना आवंटन वांछित है और इसके लिए सरकार को कठोर उपाय करने की आवश्यकता है।

– विनोद जौहरी

तेजस मार्क–1ए और 108 तेजस मार्क–2 की आवश्यकता है। उनकी चिंता को चीन की अति आधुनिक और छठे जेनेरेशन के फाइटर जेट की तैयारी को लेकर है। चीन ने पांचवीं जेनेरेशन के चेंग्डू जे–20 फाइटर जेट अपने सामरिक एअर बेस होतान और शिगात्से में पहले ही तैनात कर रखे हैं। इन तैयारियों से भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बहुत पीछे हैं।

चीन अपनी वायु सेना के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश कर रहा है और भारत की अपेक्षा कहीं अधिक। रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए रु. 6.21 लाख करोड़ का आवंटन किया था। निस्संदेह भारत ने सीमाओं पर सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और हमारी सेनाओं का सीमाओं तक द्रुत गति से युद्ध की स्थिति में पहुंचने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी संख्या में चौड़ी सड़कें, टनल, एअर स्ट्रिप, और वायु सेना के भारी भरकम विमानों के उतरने की इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने एडवांस मीडियम कंबेट एअरक्राफ्ट (एएमसीए) के लिए रु. 15000 करोड़ की लागत से प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए अनुमोदन किया जो अगले चार पांच वर्षों में पहली उड़ान भरेगा और इसका उत्पादन वर्ष 2035 में प्रारंभ होगा। रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ रु. 1,614.89 करोड़ के साथ 14 फास्ट पैट्रोल वैसेल को निर्मित करने और आपूर्ति करने का समझौता किया है।

9 जनवरी 2025 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार भारत के सुरक्षा बलों ने एक इंटीग्रेटेड सेटेलाइट कम्यूनिकेशन ग्रिड बनाने के लिए योजना बनाई है जिसमें अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहपथों (ऑर्बिट) में स्पेसक्राफ्ट स्थापित किए जायेंगे जिनका डाटा रिले सिस्टम नये युद्ध के वातावरण में उपलब्ध हो सकेगा।

सोशल मीडिया में खोयी नयी पीढ़ी में देश की सुरक्षा और स्वंय को देश की सुरक्षा के प्रति तत्पर होने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? देश की सुरक्षा पर लाखों करोड़ रुपए के निवेश के बावजूद यदि दिशाहीन और किंकर्तव्यविमूढ़ युवाओं में देश के लिए न्यौछावर होने की भावना नहीं हो, तो देश के भविष्य के लिए युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है।

4 सितंबर 2024 को प्रकाशित समाचार के अनुसार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दस कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों को अनुमोदित किया जिनका मूल्य रु० 1,44,716 करोड़ है। इन प्रस्तावों में फ्यूचर रेडी कांबेट वाहनों (एफ आर सी वी) का निर्माण है जो 1700 रूसी टैंक टी–92 को विस्थापित करेंगे। इस आवंटन में इसके अतिरिक्त एअर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार, डोर्नियर – 228 एअरक्राफ्ट, नेक्स्ट जेनरेशन फास्ट कंट्रोल और ऑफशोर पेट्रोल वेसेल की खरीद का प्रावधान है। एफ आर सी वी तीनद्य चरणों में प्राप्त किये जायेंगे जिनमें पहले चरण में 590 एफआरसीवी खरीदें जायेंगे। वास्तविकता यह है कि पूर्व सरकारों ने हमारी थलसेना, वायु सेना और नेवी को पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया। दुर्भाग्य यह भी है कि राजनीतिक पटल पर विपक्षी दल हमारी ही सेनाओं का मनोबल गिराते हैं और अपमान की भाषा बोलते हैं। किसी चुनाव में देश की रक्षा कभी किसी विमर्श में नहीं आता।

एक अन्य समाचार के अनुसार वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह ने गणतंत्र दिवस से पूर्व नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एन सी सी) के कार्यक्रम में युवा कैडेट्स को राष्ट्र निर्माण के तैयार होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं कि हर फौजी वर्दी में हो, बल्कि बिना वर्दी पहने भी प्रत्येक नागरिक देश की सेवा कर सकता है। तात्पर्य यह है कि हमारी सेनाओं की अभेद्य सुरक्षा के अलावा देश की नयी पीढ़ी और युवाओं में देश की रक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञता भी आवश्यक है। परंतु वास्तविकता यह है कि गिने चुने विद्यालयों में एन सी सी युनिट हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में खोयी नयी पीढ़ी में देश की सुरक्षा और स्वंय को देश की सुरक्षा के प्रति तत्पर होने की प्रेरणा कैसे मिलेगी ? देश की सुरक्षा पर लाखों करोड़ रुपए के निवेश के बावजूद यदि दिशाहीन और किंकर्तव्यविमूढ़ युवाओं में देश के लिए न्यौछावर होने की भावना नहीं हो, तो देश के भविष्य के लिए युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है।

देश की सुरक्षा की वृहद दृष्टि सरकार के सामने है और गंभीर चुनौतियां भी। इस वर्ष के बजट में रक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम दोगुना आवंटन वांछित है और इसके लिए सरकार को कठोर उपाय करने की आवश्यकता है। ❑❑

'वन नेशन, वन एग्जामिनेशन' से बढ़ेगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता

परीक्षाओं को लेकर देश और प्रदेशों में प्रचलित पद्धति को बार–बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। परीक्षाओं को लेकर न तो केंद्रीय स्तर पर कोई नीति बनाई गई है, और न ही राज्यों में परीक्षाओं के लिए बेहतर नीति–नियम हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने मन–मुताबिक परीक्षाओं को आयोजित करती हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि आये दिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे मेधावी छात्र–छात्राओं का मनोबल तो टूटता ही है, सरकार की भी फजीहत होती है। लेकिन, इन सब के बावजूद राष्ट्रीय या राज्यों के स्तर पर परीक्षा नीति बनाने की कोई पहल नहीं की गई। विडम्बना है कि सरकार से लेकर सहकार और अदना से लेकर खास तक सभी सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, परीक्षा की कोई बात नहीं होती जबकि शिक्षा के मूल में परीक्षा ही होती है, शिक्षा को परीक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

परीक्षा तब सुर्खियों में आती है, जब कोई पेपर– लीक हो जाता है। नहीं तो, शिक्षा और नौकरियों के बड़े–बड़े दावों के बीच परीक्षा की महत्ता और गुणवत्ता गुम हो जाती है जबकि सच तो यह है कि परीक्षा ही नौकरियों का प्रवेश द्वार है। जब प्रवेश द्वार पर ही अराजकता और अनियमितता होगी, तो प्रवेश द्वार के भीतर अपात्र लोगों का प्रवेश मिल जाएगा जिसका असर न सिर्फ देश की मेधा पर पड़ेगा, अपितु राष्ट्र का भी बड़ा नुकसान होगा। जरूरी है कि परीक्षा के लिए ऐसी कारगर नीति बने जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों वरना 'घोड़ा खाए घास और गधे को मिले च्वयनप्राश' जैसी स्थिति हो जाएगी अर्थात अयोग्य लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी और योग्य लोग धूल फांकते मिलेंगे। परीक्षा नीति बनाते समय ध्यान रखना होगा कि शिक्षा या परीक्षा माफिया के लिए व्यवस्था में सेंधमारी करना असंभव हो। प्रश्न पत्रों का सुरक्षा कवच इतना मजबूत हो कि जिसे भेदा न जा सके।

केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक परीक्षा' के तहत साल 2021 में पहला कॉमन टेस्ट कराने का वादा किया था। लेकिन चार साल में 58 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अब तक कोई टेस्ट नहीं कराया जा सका है।

– गणेश गौतम

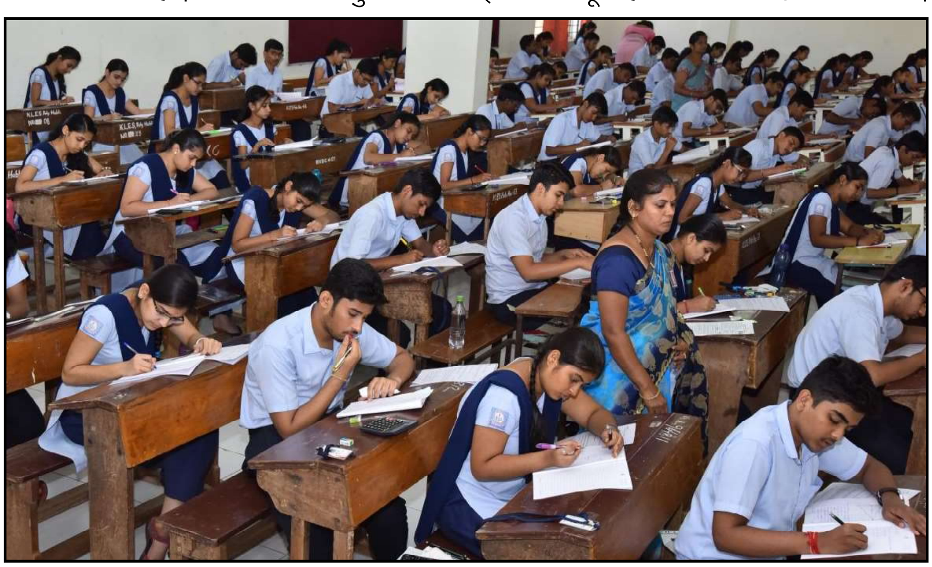

शिक्षा में परीक्षाएं ही तय करती हैं कि बेहतर शिक्षा दी गई या नहीं, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। परीक्षा के बिना शिक्षा दिशाहीन हो जाती है। वास्तविक शिक्षा का आकलन करने के लिए परीक्षा जरूरी हैं। परीक्षा से शिक्षकों को पता चलता है कि छात्रों ने विषयवस्तु पर किस स्तर तक महारत हासिल की है। शिक्षा का मूल्यांकन भी होता है। परीक्षा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाती हैं क्योंकि परीक्षा में प्राप्त अंक छात्रों को भविष्य में और बेहतर करने के लिए हौसला बढ़ाते हैं। छात्र दृढ़ता और लचीलेपन का मूल्य सीखते हैं। इससे छात्र विचारों को स्पष्ट रखने और समय का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। तात्पर्य यह कि शिक्षा के लिए परीक्षा का उतना ही महत्त्व है, जितना चंदन के लिए पानी का और दीये के लिए बाती का। ... तो फिर परीक्षा के प्रति इतनी लापरवाही और उदासीनता क्यों? यह तो वही बात हुई कि वर्षों की तपस्या के बाद वरदान प्राप्त करने का समय आया, तो आंख लग गई।

केंद्र सरकार हो, या राज्य की सरकारें, शिक्षा की बेहतरी को लेकर तो जरूर बड़ी–बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित करने को लेकर बेहतर नीति बनाई जाए, इसके लिए कहीं गंभीरता नहीं दिखती। इसलिए बात राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा एनईईटी (नीट) की करें, अथवा हाल में हुई बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की या यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। न तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाएं इससे अछूती हैं, और न राज्य स्तर पर होने वाली। मतलब, इस हम्माम में सभी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कारगर परीक्षा नीति नहीं बन पाना निराशाजनक हैं।

देश में 'वन नेशन वन इलेक्शन' की चर्चा जोरों पर है। सरकार इसके अनेक लाभ भी बता रही है। ऐसे ही 2020 में 'वन नेशन वन एग्जामिनेशन' की चर्चा खूब थी। इसी परिकल्पना के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन किया गया था लेकिन नीट–2024 में एनटीए की कितनी बदनामी हुई, वह किसी से छिपी नहीं है। इसी मंशा के साथ सरकार ने एक और प्रयास किया और 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) की मंजूरी दी गई थी। उम्मीद बनी थी कि परीक्षा के लिए कारगर नीति बनेगी और बार–बार परीक्षा देने से समय और पैसे की होने वाली बर्बादी से निजात मिल जाएगी। लेकिन चार साल बाद भी नतीजा सिफर रहा। एनआरए को जिम्मा सौंपा गया था कि वह गैर–तकनीकी पदों के लिए एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सर्विस पर्सनल की परीक्षाएं कराएगी। एनआरए के आगमन के बाद पूरी प्रक्रिया एकीकृत हो जाएगी जो छात्रों और एजेंसियों के लिए बोझिल प्रक्रिया को आसान बना देगा।

केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक परीक्षा' के तहत साल 2021 में पहला कॉमन टेस्ट कराने का वादा किया था। लेकिन चार साल में 58 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अब तक कोई टेस्ट नहीं कराया जा सका है। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग–अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न–भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग–अलग एजेंसियों के अलग–अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है, इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। परीक्षाएं आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी कार्य का बोझ बढ़ा देती हैं। एक आकलन के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है, जिनमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा नीति से देश के नागरिकों को कुछ बुनियादी अपेक्षाएं हैं जैसे कि –

1. राष्ट्रीय परीक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर ऐसे स्वायत्त संगठन का गठन किया जाए जो सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित करे,
2. यह संगठन पूरी तरह से स्वायत्त हो, जिसके पास व्यय करने के अपना धन हो और अपना मानव संसाधन भी हो,
3. इस संगठन को प्रश्न पत्र के मुद्रण से लेकर परीक्षा के सफल आयोजन तक की जिम्मेवारी हो,
4. धांधली और गड़बड़ी की स्थिति में जवाबदेही तय हो,
5. प्रश्न पत्रों के निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रश्नों के माध्यम से उम्मीदवार की मेधा की सही परख हो,
6. परीक्षा नीति निर्धारण में देश भर के केंद्रीय और राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों का सहयोग और परामर्श लिया जाए,
7. देश के मुख्य छात्र संगठनों से भी मंतव्य लिया जाए,
8. परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए विशेषज्ञ टीम हो, जिसके पास पर्याप्त अनुभव और कौशल हो,
9. राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल का निर्माण किया जाए जिसमें सुझाव देने की भी व्यवस्था हो, तथा
10. परीक्षा नीति में नई शिक्षा नीति के तहत निर्दिष्ट बिंदुओं पर गहन चर्चा हो।

❑❑

गिरती प्रजनन दर भविष्य का नया संकट

किसी भी देश का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी निर्धारित करती है। अगर आने वाली पीढ़ी पर ही खतरा मंडराने लगे, तो उस देश का सामाजिक और आर्थिक ताना–बाना विच्छिन्न होने लगता है। ऐसा ही कुछ खतरा एशिया के कुछ अमीर देशों के ऊपर मंडराने लगा है, जहां पिछले 30 वर्षों में महिलाओं की प्रजनन दर में भारी कमी आई है। जापान इस समस्या से पहले से ही जूझ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि कई अमीर एशियाई देशों की हालत तो जापान से भी बदतर है। जापान की प्रजनन दर वर्ष 1990 में 1.6 थी, जो वर्ष 2020 में गिरकर 1.3 रह गई है, जबकि चीन में यह दर 2.3 से गिरकर 1.3, सिंगापुर में 1.7 से गिरकर 1.1, हांगकांग में 1.3 से गिरकर 0.9 और दक्षिण कोरिया में 1.6 से गिरकर 0.8 रह गई है। आम भाषा में समझें तो दक्षिण कोरिया में 1990 में जहां 10 महिलाएं 16 बच्चों को जन्म देती थीं, वहीं 2020 में 10 महिलाओं ने सिर्फ 8 बच्चों को जन्म दिया। चीन में वर्ष 2021 में 1.06 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जो वर्ष 2020 की तुलना में 14 लाख कम थे। जापान में तो एक साल में सिर्फ 8 से 10 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। तुलनात्मक रूप में देखें तो इसके उलट अमरीका में एक साल में लगभग 35 से 40 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन एशियाई देशों में प्रजनन दर में कमी का कारण क्या है?

समस्या के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं। अगर सामाजिक कारणों की तरफ नजर डालें, तो सबसे पहला और प्रमुख कारण हैं कि अमीर एशियाई देशों में लोग आमतौर पर बिना शादी के बच्चे नहीं पैदा करते। जापान और दक्षिण कोरिया में सिर्फ 3 प्रतिशत बच्चे अनब्याही मांओं ने पैदा किए थे, क्योंकि कई देशों में (खासतौर पर चीन) बिना बाप के बच्चे कई अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्रतिबंध नहीं होने की वजह से पश्चिमी अमीर देशों में यह दर 30 से 60 प्रतिशत के बीच है। इसी के साथ लोगों का शादी न करना भी इस समस्या को गंभीर करता जा रहा हैं। एक अनुमान के अनुसार जापान में वर्ष 2040 तक

सवाल उठता है कि बड़ी संख्या में अविवाहित लोग समाज की संरचना को कैसे प्रभावित करेंगे? यह एक ऐसा विषय है जिस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है।

– विजय गर्ग

अविवाहित लोगों की संख्या पूरी आबादी की आधी हो जाएगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में अविवाहित लोग समाज की संरचना को कैसे प्रभावित करेंगे? यह एक ऐसा विषय है जिस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है।

आर्थिक कारणों में सबसे प्रमुख है, स्कूल की महंगी पढ़ाई। दुनिया के जिन दस शहरों में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी है, उनमें से 4 चीन में हैं और एक दक्षिण कोरिया में। जापान में स्कूलों में दाखिले के लिए तैयारी करवाने वाले कोचिंग/ट्यूशन केंद्रों, जिन्हें जुकू कहा जाता है, की संख्या वहां के स्कूलों से भी अधिक है। वर्ष 2018 में 50,000 जुकू जापान में थे, जबकि स्कूलों की संख्या 35,000 थी। महंगी पढ़ाई और इससे जुड़ी समस्याओं की वजह से वहां के लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक और आर्थिक कारण जिसने हाल ही में प्रजनन दर को प्रभावित किया है वह है, घरों की बढ़ती कीमतें। अनुसंधान से पता चलता है कि घर के महंगे होने के कारण शादीशुदा लोग बच्चे या तो देर से पैदा कर रहे हैं या निसंतान रहना पसंद कर रहे हैं। जापान में यह स्थिति इसलिए और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां पक्का घर नहीं बनाया जाता है और लकड़ी के घरों का मूल्य 22 सालों के बाद शून्य हो जाता है और इसके बाद उसे गिरा दिया जाता है। इस वजह से जापान में एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में 4 से 5 बार घर खरीदना पड़ता है।

प्रजनन दर में होने वाली कमी से उपजने वाली समस्याएं सर्वविदित हैं। जापान इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां कार्यशील लोगों पर वृद्ध लोगों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह आशंका है कि आने वाले वर्षों में जापान के पास काम करने के लिए युवा नहीं रहेंगे। अगर अब भी अमीर एशियाई देशों ने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा, तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

प्रजनन दर में होने वाली कमी से उपजने वाली समस्याएं सर्वविदित हैं। जापान इसका जीता–जागता उदाहरण है, जहां कार्यशील लोगों पर वृद्ध लोगों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह आशंका है कि आने वाले वर्षों में जापान के पास काम करने के लिए युवा नहीं रहेंगे। अगर अब भी अमीर एशियाई देशों ने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा, तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ❑❑

(विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट, पंजाब)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

सांस्कृतिक परम्पराओं के चलते पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाता भारत

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से भारत की अपनी विशेषताएं हैं, जो अन्य देशों में नहीं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए भारत में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों एवं मेलों आदि में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं द्वारा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से इन मेलों/कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है बल्कि इन श्रद्धालुओं द्वारा इन स्थानों पर किये जाने वाले खर्च से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने एवं रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित करने में भी अपना योगदान दिया जाता है। इसी प्रकार, धार्मिक पर्यटन भी केवल भारत की विशेषता है। प्रतिवर्ष करोड़ों परिवार धार्मिक स्थलों पर, विशेष महुरतों पर, पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर, वाराणसी में भगवान भोलेनाथ मंदिर, अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर, उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर, दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर आदि ऐसे श्रद्धास्थल है जहां पूरे वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले कुम्भ के मेले में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की पूजा अर्चना हेतु प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में पहुंचते हैं। 14 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुम्भ की 44 दिनों की इस इस पूरी अवधि में प्रतिदिन एक करोड़ श्रद्धालुओं के भारत एवं अन्य देशों से प्रयागराज पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुगण उक्त 44 दिनों की अवधि में प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले इन श्रद्धालुगणों द्वारा इन तीर्थस्थलों पर अच्छी खासी मात्रा में खर्च भी किया जाता है। जिससे विशेष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो बल मिलता ही है, साथ ही करोड़ों की संख्या में देश में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होते हैं एवं होटल उद्योग, यातायात उद्योग, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय, स्थानीय स्तर के छोटे छोटे उद्योग एवं विभिन्न उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारियों के व्यवसाय में भी अतुलनीय वृद्धि होती दिखाई देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव के चलते वित्तीय वर्ष 2024–25 की तीसरी एवं चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के तेज रहने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है।
–स्वदेशी संवाद

इसी प्रकार, भारत में विवाहों के मौसम में सम्पन्न होने वाले विवाहों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वर्ष 2024 के, मध्य नवम्बर से मध्य दिसम्बर के बीच, भारत में 50 लाख विवाह सम्पन्न हुए हैं। उक्त एक माह की अवधि के दौरान सम्पन्न हुए इन विवाहों पर भारतीय परिवारों द्वारा 7,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सम्पन्न हुए विवाहों पर 5,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया था। उक्त वर्णित 50 लाख विवाहों पर औसतन प्रति विवाह 14,000 डॉलर, अर्थात लगभग 13 लाख रुपए की राशि का खर्च किया गया है एवं 50,000 विवाहों पर तो एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि का खर्च किया गया है। भारत में प्रति विवाह होने वाला औसत खर्च, परिवार की औसत प्रतिवर्ष की कुल आय का तीन गुणा एवं देश में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5 गुणा के बराबर रहता है। भारत में विवाहों पर पूरे वर्ष में कुल 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन में प्रतिवर्ष विवाहों पर 17,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्ष में भारत, विवाहों पर किए जाने वाले खर्च की दृष्टि से, चीन को पीछे छोड़कर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ विवाह सम्पन्न होते हैं। भारत में सर्दियों के मौसम को विवाहों का मौसम कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर में सम्पन्न होने वाले विवाहों में से लगभग 50 प्रतिशत विवाह सर्दियों के मौसम में ही सम्पन्न होते हैं।

भारत में विवाहों पर होने वाले भारी भरकम राशि के कुल खर्च में से प्रीवेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोस्टवेडिंग फोटोग्राफी पर लगभग 10 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जाता है। विवाह के स्थान के चयन एवं साज सज्जा पर वर्ष 2023 में 18 प्रतिशत की राशि का खर्च किया गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया है क्योंकि भारतीय परिवारों द्वारा विवाह अब अन्य शहरों यथा गोवा, पुष्कर, उदयपुर एवं केरला जैसे स्थानों पर सम्पन्न किया जा रहे हैं। खानपान आदि पर कुल खर्च का लगभग 10 प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है। म्यूजिक आदि पर लगभग 6 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार, ज्वेलरी, ऑटो बाजार एवं सोशल मीडिया आदि पर भी अच्छी खासी राशि का खर्च किया जाता है। इससे, उक्त समस्त क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। अतः भारत में विवाहों के मौसम में होने वाले भारी भरकम राशि के खर्च से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को तेज करने में सहायता मिलती है।

हाल ही में सम्पन्न हुए विवाहों के मौसम में भारतीय परिवारों द्वारा किए गए खर्च के चलते अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को गति मिलेगी जो द्वितीय तिमाही में गिरकर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी। विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में विकास दर अधिक रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बंग्लादेश में राजनैतिक अस्थिरता के चलते रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयां बंद हो रही हैं एवं वैश्विक स्तर पर रेडीमेड गर्मेंट्स के क्षेत्र में कार्यरत सप्लाई चैन की इकाईयां बांग्लादेश के स्थान पर अब भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिससे भारत में रेडीमेड गर्मेंट्स एवं फूटवीयर उद्योग में कार्यरत इकाईयों को इन उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं।

उक्त कारकों के चलते भारत में परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नवम्बर 2024 माह के 58.6 से बढ़कर वर्तमान में 60.7 हो गया है। इस इंडेक्स के ऊपर जाने का आश्य यह है कि विनिर्माण के क्षेत्र में गतिविधियों में गति आ रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6.21 प्रतिशत से घटकर 5.48 प्रतिशत पर नीचे आ गया है, अर्थात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर भी नियंत्रण में आ रही है। जिससे आगे आने वाले समय में नागरिकों की खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी। हाल ही के वर्षों में विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हुए हैं और वर्ष 2005 के बाद से इस वर्ष विभिन्न कम्पनियों द्वारा सबसे अधिक नई भर्तियां, रिकार्ड स्तर पर, की गई हैं। इस सबके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2025 माह में मोनेटरी पॉलिसी में रेपो दर में कमी किए जाने की प्रबल सम्भावना बनती दिखाई दे रही है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में आ रही है। इस वर्ष भारत में मानसून का मौसम भी बहुत अच्छा रहा है एवं विभिन्न फसलों की बुआई रिकार्ड स्तर पर हुई है जिससे इन फसलों की पैदावार भी रिकार्ड स्तर पर होने की सम्भावना है। किसानों के हाथों में अधिक पैसा आएगा एवं उनके द्वारा विभिन्न उत्पादों की खरीद पर भी अधिक राशि का खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर, इन समस्त कारकों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2024–25 की तीसरी एवं चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के तेज रहने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी की कलम से)

नो डिटेंशन पॉलिसी के खात्मे से शिक्षा में होगा सुधार!

हाल ही में केंद्र सरकार (शिक्षा मंत्रालय) ने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है जिसके तहत अब कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों को फेल किया जाएगा, यह वाकई एक स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में, केंद्र सरकार के इस फैसले से बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा और ललक बढ़ेगी। नियम में बदलाव का फायदा यह होगा कि अब उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो किसी कारणवश पढ़ाई में अच्छी परफोर्मेंस नहीं दे पाते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो, इस दौरान छात्र की शिक्षा स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षकों की ओर से विशेष कोशिश की जाएगी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। शिक्षक न केवल छात्र विशेष के शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, बल्कि उनके माता–पिता, अभिभावकों को भी समय समय पर उसके बारे मार्गदर्शन व सुझाव आदि देंगे। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा में जो छात्र फेल या असफल हो जाते हैं, उन्हें फेल/असफल ही घोषित किया जाएगा और उन्हें दो महीनों के भीतर एक बार पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि वे इसमें भी फेल या असफल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। ज्ञात हो कि अभी तक आठवीं कक्षा तक फेल करने का प्रावधान नहीं था। यहां यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कक्षा विशेष में रोकने की परमिशन नहीं थी। हालांकि, अब 5वीं और 8वीं कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रोकने की परमिशन दी गई है। बहरहाल, एक और अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत किसी भी छात्र को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।

वर्ष 2010–11 से पहले पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षाओं का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2010–11 से बंद कर दिया गया था। विद्यार्थियों को अगली कक्षा

एक व्यापक व अच्छी शिक्षा प्रणाली ही हमारे शरीर, मन और आत्मा को समृद्ध करती है और हमें देश के अच्छे नागरिक बनाती है और इससे व्यक्ति, देश, समाज और राष्ट्र उन्नयन और प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं।

– सुनील कुमार महला

में प्रमोट कर दिया जाता था। इससे स्कूली शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ गई थी। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर भी कमोबेश पड़ा और नतीजे खराब आ रहे थे। यहां तक कि राज्य सरकारें भी पहले से जारी व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति में थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य चाहें तो परीक्षा करा सकते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि केंद्र सरकार ने कक्षा 5 व 8 के छात्रों को अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म करने के संबंध में शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव करके इसे वर्ष 2019 में ही अधिसूचित कर दिया था, लेकिन देश के बहुत से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसे अपनाये हुए हैं।

गौरतलब है कि जुलाई 2018 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोकसभा में शिक्षा का अधिनियम, 2009 के संशोधन पर अपनी बात रखते हुए यह कहा था कि 'कई सरकारी स्कूल अब मिड डे मील स्कूल बन गए थे क्योंकि इनमें शिक्षा और सीखना ग़ायब है।' गौरतलब है कि उस समय केंद्र में नो डिटेंशन पॉलिसी थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने पांचवीं और आठवीं कक्षा के लिए हटा दिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा संविधान में आज समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। अब केंद्र सरकार ने शिक्षा (पांचवीं/आठवीं कक्षा के बच्चों) के संदर्भ में यह निर्णय लिया है कि कमजोर छात्रों की मॉनीटरिंग हो और इनकी कमजोरी को चिह्नित कर अभिभावकों की मदद से इन छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार किए जा सकें। यह पॉलिसी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय व सैनिक स्कूलों सहित सरकार द्वारा संचालित तीन हजार से ज्यादा स्कूलों में लागू होगी।

शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का किसी राष्ट्र का प्रमुख आधार स्तंभ होती है, विकास की असली रीढ़ होती है। आज भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कमोबेश मैकोले शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। अतः आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ठोस कार्य हों।

कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से सवाल उठाये जा रहे थे। अब नई पालिसी से शिक्षा में पहले से कहीं अधिक सुधार होगा। यह भी कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का किसी राष्ट्र का प्रमुख आधार स्तंभ होती है, विकास की असली रीढ़ होती है। आज भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कमोबेश मैकोले शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। अतः आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ठोस कार्य हों।

शिक्षा पद्धति को जटिल नहीं अपितु सरल होना चाहिए अथवा उसमें ऐसा समावेश किया जाना चाहिए, जिससे छात्र सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ें। नीरस और स्तरहीन शिक्षा का कोई औचित्य नहीं होता। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक पद्धतियों का समावेश किया जाए। आज के परिवेश में छात्र अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में विभिन्न संसाधनों इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शिक्षकों की कमी आदि पर भी आज ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा में पर्यावरण, प्रकृति व खेल को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा से जुड़ें।

हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि आज शिक्षा का अधिकार जितना अहम है, उतना ही उसकी गुणवत्ता में कंट्रोल भी जरूरी और अति आवश्यक है। बिना गुणवत्ता वाली शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। समाज को भी यह समझना होगा कि अनुत्तीर्ण छात्र को अनुत्तीर्ण करना ही उचित व सही है। अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने से शिक्षा में गुणवत्ता कहां से आएगी ? अनुत्तीर्ण छात्र की शिक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है, उसे अभ्यास और मेहनत से नये आयामों की ओर ले जाया जा सकता है।

कहना ग़लत नहीं होगा कि आज शिक्षा प्रणाली में निश्चित ही आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, बहुत से सुधार किए गए हैं, लेकिन आज भी शिक्षा में और भी बहुत से सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षा को छात्रों को व्यावहारिक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और दूसरों पर कम निर्भर हों। सच तो यह है एक व्यापक व अच्छी शिक्षा प्रणाली ही हमारे शरीर, मन और आत्मा को समृद्ध करती है और हमें देश के अच्छे नागरिक बनाती है और इससे व्यक्ति,देश, समाज और राष्ट्र उन्नयन और प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं।❑❑

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

ईश्वर के आंनद, स्वामी विवेकानन्द

12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में अवतरित वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली, आध्यात्मिक गुरु, स्वामी विवेकानन्द का बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किन्तु उनका औपचारिक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। 30 वर्ष का अल्पायु में उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द की वक्तृता के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी जगत के कल्याण के लिए क्रियाशील है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें विश्व धर्म महासभा में 2 मिनट का समय दिया गया था किन्तु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरम्भ "मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों" के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था।

अलौकिक, 4 जुलाई 1902 को देवलोकगामी 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवनकाल में स्वामी विवेकानन्द जो काम कर गये वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था– "यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।" रोमां रोलां ने उनके बारे में कहा था "उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असम्भव है, वे जहाँ भी गये, सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नायक का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के आनंद, स्वरूप थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा–'शिव!' यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो।"

अभिभूत, स्वामी विवेकानन्द केवल सन्त ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव–प्रेमी भी थे। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन–समर्थन मिला, वह विवेकानन्द के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है। उनके कथन ""उठो! जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर–जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।" अजर–अमर है। जो उनकी जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर सार्थक होगा। यथेष्ट, स्वामी विवेकानंद ने और कहा था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। स्तुत्य, स्वामी जी ने जन जागरूकता बढ़ाने, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रवाद के विचार में अतुलनीय योगदान दिया। जो मानव कल्याण के निहितार्थ सदा–सर्वदा कालजयी है। ❑

प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। स्तुत्य, स्वामी जी ने जन जागरूकता बढ़ाने, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रवाद के विचार में अतुलनीय योगदान दिया। जो मानव कल्याण के निहितार्थ सदा–सर्वदा कालजयी है।

– **हेमेन्द्र क्षीरसागर**

नेताजी रहते तो होता नव सुभाष

नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता महाभियान के क्रांतिकारियों में से एक आजाद महानायक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। जो विशेषतः आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध थी। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओड़िशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ ने अंग्रेजों के दमनचक्र के विरोध में 'रायबहादुर' की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प ले, चल पड़े राष्ट्रकर्म की राह पर। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा– 'जब तुमने देशसेवा का व्रत ले ही लिया है, तो कभी इस पथ से विचलित मत होना।'

सुभाष ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में 'भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन' के साथ हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हाल के सामने 'सुप्रीम कमाण्डर' के रूप में सेना को सम्बोधित करते हुए "दिल्ली चलो!" का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कामनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया।

5 जुलाई 1943 को 'आजाद हिन्द फौज' का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आजादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे जिनकी निडर देशभक्ति ने उन्हें देश का हिंदू बनाया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा" सुभाष चंद्र बोस का यह प्रसिद्ध नारा था।

रंगून के जुगनी हाल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। जिसमें उन्होंने कहा था कि "स्वतंत्रता बलिदान चाहती है अपनी आजादी के लिए बहुत त्याग किया है। किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है" ये आजाद की वचन थे। उन्होंने आजादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। जो अपना सर काट के स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सके। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीयता की पहचान ही बन गए और भारतीय युवक आज भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करती है।

सुभाष चंद्र बोस भारत के अमूल्य ही थे, जो जय हिंद का नारा और अभिवादन देकर चले गए। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना से हो गई थी। लेकिन क्या उनकी सच में मृत्यु हुई थी, ये गुत्थी सुलझ नहीं सकी। यदि यह रहस्य उजागर हो जाता तो असलियत देश के सामने आ जाती। काश! आजादी के बाद नेताजी जीवंत रहते तो देश का नव सुभाष होता। ❑❑

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार)

स्वदेशी जागरण मंच ने मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से संचालित स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत विवेकानन्द जयंती के पूर्व दिवस के 'स्वावलंबी युवा दिवस' के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनीत चतुर्वदों ने की, जबकि मुख्य अतिथि एसडीएम बिजनौर अवनीश कुमार रहे। कार्यक्रम का संचालन लघु उद्योग भारती के मंत्री और स्वावलंबी भारत अभियान के जिला संयोजक मणि खन्ना ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने बताया कि स्वरोजगार के लिए सुंदर वातावरण बनाने, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी आयोग के गठन की मांग को लेकर ऑनलाइन पिटिशन आप सभी के डिजिटल हस्ताक्षर करवाकर भारत सरकार को भेजी जाएगी। युवा उद्यमियों में चांदपुर से शांतनु अग्रवाल काजू प्रोसेसिंग, नजीबाबाद से शोभित, अम्बिका प्लाईवुड और मोहित अग्रवाल टाइल मनुफेकवर धामपुर से अमोघ हर्ष गोयल एका फूड एंड देवरेज, बिजनौर से प्रभात वशिष्ठ रेडी टू मूव कंक्रीट, रश्मि राजपूत क्लैम्प मैन्युफैक्चरिंग, गुरवश सिंह रस्क फैक्ट्री के साथ साथ स्वदेशी पद्धति, योग के लिए भारद्वाज और आयुर्वेद के क्षेत्र में डा. गौरव सिंघल को सम्मानित किया।

स्वावलंबन रैली से दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

स्वदेशी जागरण मंच, जयपुर प्रांत का दो दिवसीय प्रांत सम्मेलन आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में संपन्न हुआ। इसके तहत स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी स्वावलंबन रैली निकाली गई। हाथों में स्वदेशी अपनाने का संदेश देती तख्तियां लेकर रैली बिजली घर चौराहा, होप सर्कस होती हुई भगत सिंह सर्किल पहुंची। यहां स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने दत्तोपंत ठेगड़ी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि ठेगड़ी एक बहुत

अच्छे संगठक, विचारक और चिंतक थे। कम्युनिस्टों के बारे में वे कहते थे कि वामपंथी विचारधारा यह एक गलत धारणा पर आधारित है और स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चीन भी कम्युनिज्म छोड़ आज पूंजीवादी हो चुका है।

उन्होंने कहा कि आज भारत तभी आगे बढ़ेगा, जब स्वरोजगार बढेगा और आज का युवा रोजगार प्रदाता बनेगा। स्वावलंबी भारत अभियान की महिला सह समन्वयक प्रमुख अर्चना मीणा जी ने कहा कि अभियान के तहत देश के 400 जिलों में केंद्र स्थापित किए हैं जहां पर लोगों को रोजगार के बारे में जानकारी मिल रही है। इस अवसर पर क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, प्रांत संयोजक सुरेन्द्र नामा, प्रांत समन्वक लोकेंद्र सिंह नरूका, प्रांत सहसंयोजक विनोद पाल यादव, संपर्क प्रमुख राजेश कुमार शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

स्वदेशी उत्पाद व उद्यमिता के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू

स्वदेशी व स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान के तहत डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत युवाओं से डिजिटल हस्ताक्षर करवाकर उन्हें उद्यमिता, स्वरोजगार व स्वदेशी के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के पहले दिन एक हजार युवाओं से अधिक डिजिटल हस्ताक्षर करवाए गए। यह अभियान एक महीने तक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व व्यापारिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख अनिल गोयल ने बताया कि डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य हर घर स्वदेशी व हर युवा को रोजगार मिले। इसके साथ ही उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा मिले और हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल अपने देश में बनी वस्तुओं के क्रय–विक्रय का ही नाम नहीं बल्कि यह स्वदेशी आचार– व्यवहार, संस्कृति, वेशभूषा व व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में प्रकट करने का विषय है। यह देशभक्ति की साकार अभिव्यक्ति है। इसलिए हर घर में स्वदेशी का प्रयोग, जीवन के हर क्षेत्र में स्व का भाव ही स्वदेशी है। उन्होंने बताया कि हिसार में युवती प्रमुख सोनिया श्योदान ने आईकेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचकर युवाओं के डिजिटल हस्ताक्षर करवाए और उन्हें स्वदेशी उत्पादों की जानकारी दी। इसी भांति अन्य कार्यकर्ताओं ने भी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करके अपनी–अपनी भूमिका निभाई।

राष्ट्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवाओं के कंधे परः मंडलायुक्त

स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर टिमिट सभागार में युवा सम्मान समारोह एवं डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर हुआ।

मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त अनंजेय कुमार ने कहा कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर हैं। अपने युवा अपने आदर्श तार्किकता के साथ चुने। कोई एक्टर या खिलाड़ी किसी विशेष विद्या में पारंगत हो सकता है परंतु उसका व्यक्तित्व अनुकरणीय हो ऐसा नहीं है। इसलिए अपना आदर्श या हीरो व्यक्तित्व के आधार पर चुने जैसा कि स्वामी विवेकानंद थे। आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है, इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़े।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नवनिर्वाचित कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि आज का युवा अपनी दिशा तय करने में भ्रमित है। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ राजीव कुमार ने युवाओं में उद्यमिता की मानसिकता विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के तहत एक देशव्यापी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य स्वदेशी एवं उद्यमिता के प्रति जागरूकता एवं केंद्र सरकार और राज्य

सरकार से उद्यमिता आयोग का गठन करने के हेतु प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि पूरे देश से एक करोड़ हस्ताक्षर इस अभियान में करने का लक्ष्य है।

वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज गुप्ता ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर देश और धर्म के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने भी अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादाई व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद जिले से एक लाख हस्ताक्षर इस अभियान के अंतर्गत कराए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट शिशिर गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी का आभार व्यक्त किया।

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 13 युवाओं को सम्मानित किया गया। आचार्य अमित शर्मा (धर्म प्रसार), डॉ अंजु सिंह (प्रशासनिक सेवा), डॉ अनुपम अग्रवाल (चिकित्सा), पुष्पांजलि सिंह (खेल), रोहित सिंह (उद्यमिता), मयंक शर्मा (साहित्य), निमित जायसवाल (पत्रकारिता), मनदीप सिंह (चित्रकारिता), अभिव्यक्ति सिंह (साहित्य सृजन), अंकुर त्यागी (जैविक कृषि), नेहा श्योरान (योग), ऐश्वर्या गोयल (वाणिज्य), नेपाल सिंह पाल (पर्यावरण) को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रांत अभियान समन्वयक कुलदीप सिंह एवं संयोजन विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ ए अग्रवाल, अंजू त्रिपाठी, पूनम चौहान, मीनू अरोड़ा, नीरज सोलंकी नीलम जैन, प्रदीप शर्मा, राजेश खन्ना, सौरभ चौधरी, पुष्पा सोलंकी, राजेश विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के अग्रवाल, कशिश चौहान, योगेंद्र सिंह लिए 13 युवाओं को सम्मानित किया, राजीव सक्सेना, गुरप्रीत सिंह दुआ, गया आचार्य अमित शर्मा (धर्म एडवोकेट रणजीत सिंह, आदि रहे।

22वां इस्पतांचल स्वदेशी मेला संपन्न

10 दिवसीय 22वां इस्पतांचल स्वदेशी मेला भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक वीरेंद्र कुमार तिवारी उपस्थित

रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत कोश प्रमुख विष्णु कुमार सिंह ने की, वहीं संचालन प्रांत संपर्क प्रमुख अजय चौधरी "दीपक" ने किया, जबकि स्वागत एवं विषय प्रवेश मेला संयोजक ब्रिजेश कुमार सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला संयोजक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया।

मुख्य अतिथि बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक वीरेंद्र कुमार तिवारी ने युवाओं से स्वदेशी के प्रति संवेदन होने की अपील की। उन्होंने खुलकर युवाओं से कहा की हमें पुनः विश्व गुरु बनना है तो अपने सोच के साथ अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाना होगा। हमारे यहां विश्व की सबसे बड़ी मानव संख्या है। उद्यमियों के लिए सकारात्मक रूप से देखने का नजरिया होनी चाहिए कि यह बहुत बड़ी बाजार है। उन्होंने खुलकर युवाओं से कहा कि वह नौकरी का सपना छोड़ रोजगार देने वाला बनने की सोच को अमल में लाएं।

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सह संघर्ष वाहिनी प्रमुख बंदे शंकर सिंह ने कहा कि हमारे विचार को वामपंथी हो या दक्षिणपंथी सभी ने सहर्ष स्वीकार किया है। विचारधारा कोई भी हो राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वदेशी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को एक परेशानी होती थी कि स्वदेशी वस्तु की पहचान व जानकारी के अभाव में विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके समस्या को समाधान करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों के लिए मेला के माध्यम से एक मंच मुहैया करा रही है।

क्षेत्रीय संयोजक अमरेंद्र कुमार सिंह ने भी स्वदेशी के प्रति अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में मिला के दौरान विभिन्न तरह के आयोजित कार्यक्रम के प्रथम विभागियों के बीच प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार वितरण किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में विवेकानंद झा, अशोक रंजन, किशोर कुमार बोराल, विनोद चौधरी, सुरेश कुमार सिन्हा, राकेश रंजन, प्रेम प्रकाश अवधेश कुमार, मनिष श्रीवास्तव, अमर जी सिन्हा, सौरभ जयसवाल, कुमार संजय, सुजीत कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार, दिपक कुमार, पुनम सिन्हा, अनुजा सिंह, मनोरमा चौधरी, राधा सिंह, निलम सिंह, नूतन वर्मा, आशा सिन्हा, रिता सिन्हा सहित सभी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हिमाचल प्रान्त का सम्मेलन हमीरपुर में संपन्न

स्वदेशी जागरण मंच, हिमाचल प्रान्त का सम्मेलन हमीरपुर के बसंत पैलेस में हुआ, जिसमें मुख्यातिथि के रूप में अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने शिरकत की। उनके साथ उतर क्षेत्र के संगठक श्री विनय, महिला प्रमुख रूपा, डॉक्टर जय देव हिमाचल प्रांत के संयोजक गौतम, सह संयोजक सुनील, हिमाचल प्रान्त के संगठन मंत्री जसवंत कार्यकर्म अध्यक्ष नवीन शर्मा सहित स्वदेशी जागरण मंच के 200 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर स्वदेशी व स्वावलंबन को बढ़ावा देने वालों को सम्मानित किया गया साथ ही उन्होंने स्वावलंबन के प्रति अपने अनुभव व विचार भी प्रकट किए। अखिल भारतीय सह संघठक सतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश व प्रदेश का युवा बहुत ही होनहार है और रोजगार के लिए स्वरोजगार को अपनाए इस विषय पर सम्मेलन में प्रकाश डाला उन्होंने कहा युवाओं के साथ साथ हमारी मातृ शक्ति भी स्वरोजगार के लिए निपुण है और आज कल हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें हमारे युवा वर्ग व मातृ शक्ति ने स्वरोजगार का रास्ता अपना कर औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी ,स्वावलम्बन व उद्यमिता के ऊपर प्रकाश डाला गया उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा रोजगार के लिये ना भाग कर स्वरोजगार को अपनाए। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तबसे उन्होंने वोकल फ़ॉर लोकल का नारा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए दिया था और देश के युवाओं को स्किलड बनाने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जिससे देश में स्वरोजगार के नए आयाम स्थापित हुए हैं । नवीन शर्मा ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं।

https://www.amarujala.com/video/himachal-pradesh/hamirpur-hp/video-the-conference-of-all-india-swadeshi-jagran-manch-himachal-pradesh-was-concluded-in-hamirpur

उद्यमिता बढ़ावा हेतु राज्यपाल से भेंट

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच तेलंगाना क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद के राजभवन में राज्य के राज्यपाल विष्णु देव वर्मा से शिष्टाचार भेंट की।

बैठक के दौरान, सतीश ने तेलंगाना में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर चर्चा की।

इसके अलावा, चर्चा में स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियाँ शामिल थीं। इसके अलावा, करीमनगर में आयोजित होने वाले आगामी स्वदेशी मेले का विवरण राज्यपाल के साथ साझा किया गया और उन्हें विशेष कार्यक्रम में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में स्वदेशी जागरण मंच के राज्य संयोजक हरीश बाबू, स्वावलंबी भारत अभियान के सह–संयोजक बी इंद्रसेन रेड्डी, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख केशव सोनी शामिल थे; और स्वावलंबी भारत अभियान के सदस्य सुधाकर शर्मा और महेश।

https://jantaserishta.com/local/telangana/promoting-3793121

स्वदेशी को आगे बढ़ाने से ही समृद्ध होगा देश

स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा की बैठक सहसंयोजक

श्यामल दास की अध्यक्षता में कैफेटेरिया में आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन अजय उपाध्याय उपस्थित हुए। बैठक का शुभारंभ स्वदेशी जागरण मंच संस्थापक राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित सचकर किया गया। बैठक में विभिन्न कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया। जिला संयोजक रामावतार राम रवि सह संयोजक जय किशन बिरूली श्यामल दास जिला संपर्क प्रमुख दिलीप साव जिला युवा प्रमुख रोहित दास जिला महिला प्रमुख शांति देवी जिला विचार विभाग प्रमुख अजय गोप जिला संघर्ष वाहिनी प्रमुख अनूप प्रसाद जिला प्रचार प्रमुख केशव प्रसाद जिला मीडिया प्रभारी राकेश पोद्दार जिला कोषाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा स्वावलंबी भारत अभियान के लिए संयोजक मिलन महतो सह संयोजक अमित कुमार नाग को बनाया गया। उपाध्याय के द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज देश में स्वदेशी जागरण मंच की आवश्यकता और बढ़ गई है क्योंकि हम सब कार्यकर्ता बंधु ही स्वदेशी के भाव को जन–जन तक पहुंचा सकते हैं। समाज के बीच हमें संवाद निरंतर बनाए रखना है और स्वदेशी प्रेम को स्वदेशी भाव को आगे बढ़ाना है।तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है। इसके लिए कई अहम विषय हैं जैसे खेती को प्रकृति युक्त बनाना होगा। पशुधन को स्वदेशी रूप में आगे बढ़ना होगा। जो बागवानी हम सब करते हैं उसे औषधि युक्त बागवानी बनाना है। बाजार को स्वदेशी युक्त बनाए रखना है विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना है स्थानीय उत्पादों का उपयोग एवं प्रोत्साहन करना होगा साथी मोटे अनाज की और हम सभी को आकर्षित रहना है और रहने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। बैठक में डॉ अनिल राय कौशल किशोर प्रताप कटियार महतो अजय गोप कामेश्वर विश्वकर्मा देव कुमार प्रकाश महतो राकेश पोद्दार श्यामल दास दिलीप साव अनुप प्रसाद दुर्योधन पान अमित नाग जय किशन बिरूली रोहित दास व्यास निषाद यश खान्डाईत अश्विनी खलको पप्पू राय मुख्य रूप से उपस्थित थे।

https://www.livehindustan.com/jharkhand/chaibasa/story-swadeshi-jagran-manch-meeting-in-chaibasa-emphasizing-indigenous-development-201735553934901.html

स्वावलंबन एवं उद्यमिता से मजबूत होगी आर्थिक स्थितिः धर्मेंद्र दुबे

सीकर (सुमेर सिंह राव) रामलीला मैदान स्थित समुत्कर्ष भवन संघ कार्यालय में स्वदेशी जागरण मंच दो दिवसीय युवा सम्मेलन रविवार को सम्पन्न हुआ। विभिन्न सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत और

भारत में फैल रही बेरोजगारी की विकराल समस्या से छुटकारा दिलाएगा। बेरोजगारी भारत का सबसे बड़ा दर्द है। स्वावलंबन एवं उद्यमिता से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्षेत्रीय संयोजक श्री सतीश कुमार आचार्य ने कहा कि कृषि लघु एवं कुटीर उद्योग प्रारंभ से ही देश की रीड की हड्डी रही है। पूर्ण रोजगार का चतुष् पंक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसमें विकेंद्रीकरण स्वदेशी उद्यमिता एवं सहकारिता प्रमुख है।

स्वावलंबी भारत अभियान एवं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सहसंयोजक लोकेंद्र सिंह ने उद्यमिता का मार्ग स्थानीय स्वदेशी सहकारिता चीन से रोजगार की चुनौती विश्व में उपलब्ध रोजगार युवाओं का नौकरियों के प्रति दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने देश के युवा रोजगार प्रदाता उद्यमियों एवं फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले सफल उद्यमियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये। प्रशिक्षण शिविर में प्रांत युवा कार्य प्रमुख मोहित सैनी, विभाग प्रचार प्रमुख एवं पर्यवेक्षक विक्रम शर्मा श्रीमाधोपुर, विभाग संयोजक निर्मल सिंह अजीतगढ़, सीकर जिला संयोजक जितेंद्र सिंह, जिला सहसंयोजक आदित्य कुमार उर्फ मंथन,अर्जुन सिंह, कुलदीप सिंह शेखावत, नीमकाथाना जिला संयोजक इंद्राज गुर्जर, जिला सहसंयोजक सुशील कुमार रामूका, स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के पूर्णकालिक कार्यकर्ता ब्रह्मदत्त मीणा सहित प्रांत के अनेक युवाओं ने प्रशिक्षण में भाग लेकर स्वदेशी का संकल्प लिया। इसके बाद सभी ने जीण माता के दर्शन किए।

https://gexpressnews.com/44733#google_vignette

स्वामी विवेकानंद ही हैं हिंदुत्व की आवाज और युवाओं के आइकॉनः अमरेंद्र सिंह

'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं' का जयघोष पूरे विश्व में फैलाने वाले तथा अमेरिका में जाकर हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले युवाओं के आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर देश के कौने—कौने, हर नगर—कस्बे में डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हो रहा है। उपरोक्त कहना है स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक अमरेंद्र सिंह का। श्री सिंह मजदूर मैदान में चल रहे स्वदेशी मेला में आयोजित कार्यक्रम स्वावलंबी भारत अभियान में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रुप में मनाते आ रही है। इस वर्ष विवेकानंद जयंती को युवा संकल्प दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके निमित्त 12 जनवरी से 12 फरवरी तक डिजिटल हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलाया जाएगा। जिसके माध्यम से देश की युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हमारा संकल्प है, हर घर स्वदेशी, हर युवा को रोजगार मिले, दूसरा उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम तथा युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार निर्माण व प्रदेश और केंद्र स्टार पर उद्यमिता आयोग का गठन आदि शामिल है।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि बोकारो कवियों की भूमि है। यहां इस्पात तो बनता ही है लेकिन इसके साथ साहित्यकार, रचनाकार और कवियों का भी निमार्ण होता है। पूर्व सांसद ने सभी प्रतिभागियों को स्मृतिचिन्ह भी वितरित की। ग्रंथ सृजन संस्थान के संस्थापक रजत नाथ ने कहा कि कला और साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। मन की भावनाओं को जब आप शब्दवाली में बांध देते हैं तो वो काव्य बन जाता है। सेक्टर चार, मजदूर मैदान में आयोजित काव्य गोष्ठी में बोकारो, हजारीबाग, धनबाद सहित एक दर्जन से भी ज्यादा कवि कवियित्रियों ने अपनी रचना का पाठ किया और दर्शकों को बांधा रखा। इस अवसर पर विवके सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण के पूर्व ओएसडी, बेहतर झारखंड के संयोजक और समाजसेवी ने क्रोध और द्वंद, गीता कुमारी गुस्ताख ने आओ चलकर ढ़ढें गाँव में पीपल की छांव, लव कुमार ने आजकल, रजत नाथ ने कभी दुखों का पहाड़ है, कभी आँसूओं का सैलाब है, मनसा कृष्णा ने सागर से भी गहरा, ज्योति वर्मा ने आती थी याद लेकिन मजबूर दिल न माना, अमृता शर्मा ने शर्माईन सा वैलेंटीन, सुप्रिया सरस ने थोड़ी से बदतमीजी मुझे भी सिखाई होती, धनबाद की चंदनी वर्मा ने मन जिताए मन हराए, मन ही कराए प्रीत, जादूगर सरोज राय ने जिस पार्टी में मैं जाता हूँ। जैनामोड़ की सुजाता कुमारी ने खोरठा काव्य हमनी के झारखंड, कल्पना केसर ने प्रेम का एहसास काव्य पाठ किया। मंच का संचालन गीता कुमारी गुस्ताख और लव कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन ज्योति नाथ ने किया। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांत सम्मेलन

सचित्र झलक

अलवर, जयपुर

हिमाचल प्रदेश

स्वदेशी मेला - झारखंड

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जनवरी 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697 / 96

स्वदेशी गतिविधियां

हस्ताक्षर अभियान

(12 जनवरी – 12 फरवरी 2025)

सचित्र झलक

जमशेदपुर

सिक्किम

त्रिपुरा

उत्तर बिहार

केरल

रामगढ़, झारखंड

झुंझुनूं, राज.

दमोह, म.प्र.

मुरादाबाद, उ.प्र.

बलिया, उ.प्र.

शाहजहांपुर, उ.प्र.

बृज

लुधियाना, पंजाब

संगरिया, राज.

आजमगढ़

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती